page 1 and 8 jan 25_page 1 Mar 25 final ds.qxd 26-01-2025 01:01 Page 1

epaper.dehatsandesh.com

देहात संदेश की और से सभी पाठकों व राज्यवासियों के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं

3 जीजीएम साइंस कॉलेज में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस

5 नयना और हर्षित ने आइस स्केटिंग में जीते स्वर्ण पदक

8 उपराज्यपाल जम्मू में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शामिल हुए

मौसम जम्मू न्यूनतम 8 अधिकतम 19

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-25 | जम्मू तवी, रविवार 26 जनवरी, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह)4 रूपये | पृष्ठ -8

'पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण आज हड़ताल की जगह सड़कों पर हर्षोल्लास है'

जम्मू, 25 जनवरी।

प्यारे भाइयो और बहनों,

1. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको कोटि-कोटि शुभकामनाएं। हर एक नागरिक के लिए गणतंत्र दिवस का पावन पर्व संविधान में निहित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्शों में अपनी आस्था मजबूत करने का अवसर है। यह पर्व समावेशी और सांस्कृतिक विकास की धारा को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का अवसर है।

2. मैं आर्मी के सभी जवानों, अर्धसैनिक बलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस के शूरवीरों को उनके त्यागू, पराक्रमऔर निःस्वार्थ सेवा के लिए शत-शत

नमन करता हूँ। उनके अपराजित पौरुष ने आतंकवाद और अलगाववाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। नार्को-टेरर नेटवर्क पर अंकुश लगाया गया है। पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण आज हड़ताल की जगह सड़कों पर हर्षोल्लास है। नौजवानों के हाथ में पत्थर नही, पुस्तक है। आतंक और भय-मुक्त जम्मू-कश्मीर की कल्पना को अपने रक्त से साकार करने वाले शहीदों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ।

3. मैं जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक, किसान, कारीगर, साहित्यकार, कलाकार, कामगार, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, वैज्ञानिक, उद्यमी, हस्तशिल्पी, नारी शक्ति, नौजवान, सुरक्षा बलों और खिलाड़ियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका समर्पण और मेहनत हमारी सामूहिक सफलता की आधारशिला है।

4. प्यारे भाइयो और बहनों, विविधता में एकता अनादि- काल से जम्मू-कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति- रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्व-धर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। विकास की निरंतर गति को बनाए रखने के साथ-साथ, एकत्व की इस पवित्र भावना को भी नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना होगा।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

ऊंची आर्थिक विकास दर से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं : मुर्मु

नयी दिल्ली 25 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को कहा कि हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, किसानों और मजदूरों के हाथों में अधिक पैसा आया है तथा बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि साहसिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधारों के बल पर आने वाले वर्षों में प्रगति की यह रफ्तार बनी रहेगी। समावेशी विकास प्रगति की आधारशिला है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचता है।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि सरकार ने वित्त के क्षेत्र में जिस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, वह एक मिसाल है। डिजिटल भुगतान के विभिन्न विकल्पों के साथ-साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को औपचारिक तंत्र में शामिल किया जा सका है। इसके कारण तंत्र में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। इस प्रक्रिया में, कुछ वर्षों के दौरान ही एक ऐसा मजबूत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया है जो विश्व की श्रेष्ठतम संरचनाओं में से एक है।

उन्होंने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रापसी संहिता जैसे साहसिक उपायों के परिणामस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था अब अच्छी स्थिति में आ गई है। इससे वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सड़कों और रेल मार्गों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक हब सहित फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। इससे एक ऐसा मजबूत आधार विकसित हो

(शेष पृष्ठ 8 पर)

एसआईटी ने राजौरी में मौतों के मामले में आपराधिक पहलू की जांच की

जम्मू, 25 जनवरी । राजौरी जिले के बदहाल गांव में 17 लोगों की मौत के बाद, अधिकारियों ने मृतकों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन के अंश पाए जाने के बाद संभावित आपराधिक गतिविधि की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

एक अधिकारी ने बताया कि एसआईटी ने मामले के संबंध में अब तक 50 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की है जिसका उद्देश्य दुखद घटना से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी का पता लगाना है।

इसके समानांतर पीड़ितों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें क्वारंटीन करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं जिनमें अस्पताल जाने और शवों को दफनाने वाले लोग भी शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि मौतों

(शेष पृष्ठ 8 पर)

जम्मू-कश्मीर पुलिस पर पुरस्कारों की बौछार, 27 पुरस्कार मिले -सबसे अधिक 15 वीरता पदक भी शामिल

जम्मू, 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पदक से सम्मानित किए गए जम्मू-कश्मीर के 15 पुलिस अधिकारियों में से सात जिनमें कश्मीर क्षेत्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार भी शामिल हैं ने तीन साल पहले अमरनाथ यात्रा पर संभावित आतंकी हमले को टालने में अहम भूमिका निभाई थी ।वीरता पदक प्राप्त करने वालों में पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट भी शामिल हैं जो सितंबर 2023 में दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले चार अधिकारियों में से एक थे। भट को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर असाधारण बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। 15 वीरता पदकों के अलावा आनंद जैन और नीतीश कुमार दो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला जबकि

(शेष पृष्ठ 8 पर)

15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शपथ दिलाई

जम्मू 25 जनवरी। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पर नागरिक सचिवालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

अधिकारियों ने शपथ ली कि वे भारत के नागरिक होने के नाते लोकतंत्र में दृढ़ विष्वास रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हेतु प्रयास करने की शपथ लेते हैं और धर्म, समुदाय और भाषा की परवाह किए बिना निर्भीक होकर अपना वोट डालेंगे। इस वर्श की थीम वोटिंग से बढ़कर कुछ नहीं, मैं जरूर वोट दूंगा पिछले वर्श की तरह ही है। यह मतदाताओं के धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी डर या पक्षपात के बिना स्वतंत्र रूप से चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के महत्व पर प्रकाश डालता है। (शेष पृष्ठ 8 पर)

कटड़ा से बडगाम तक वंदे भारत का ट्रायल रन सफल

श्रीनगर, 25 जनवरी । श्रीमाता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन, कटरा से बडगाम तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एकतरफा ट्रायल रन आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रेन शुक्रवार को जम्मू संभाग में पहुंची थी। उसके बाद शनिवार को श्रीनगर पहुंची है। वंदे भारत एक्सप्रेस आईसीएफ ट्रेन 49 और 80 को यूएसबीआरएल सेक्शन में वाणिज्यिक संचालन के लिए निर्धारित किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सर्दियों के मौसम में ठंडी परिस्थितियों के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें आराम, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित

करने के लिए उन्नत तकनीकें हैं। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन भारत के पहले केबल-स्टेड रेल ब्रिज, प्रतिष्ठित अंजी खाद ब्रिज और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज से भी गुजरी। कश्मीर घाटी की ठंडी जलवायु का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है।

26 त्यौहारों जैसी क्यों नहीं मनती जनवरी!

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। बस तभी से देश गणतंत्र हुआ और उसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान, इसी दिन अस्तित्व में आया और गणतान्त्रिक देश बना। गणतंत्र दिवस पूरे देश में बहुत उत्साह और विशेष रूप से राजधानी में एक साथ मनाया जाता है। दिल्ली में एक विशाल समारोह होता है जो हमें देश के लिए बलिदान देने वालों की याद दिलाता है। इस दिन राष्ट्रपति वीरता के विभिन्न कार्य करने वालों को बहादुरी के लिए पदक देकर उनका सम्मान करते हैं। राजघाट से है, विजयपथ तक अपनी वेशभूषा में सजीधजी सेना की विभिन्न रेजीमेंटों, नौसेना, वायु सेना, घुड़सवार सेना व देश के कोने-कोने से आई प्रदेशों की झांकियां निकलती हैं। इस समारोह में देशभर से आए स्कूली बच्चे, एनसीसी के छात्र राजधानी में इकट्ठे होते हैं जो महीनों से 26 जनवरी की तैयारी में जुटे रहते हैं।

ऐसा हो गणतंत्र हमारा

ऐसा हो गणतंत्र हमारा
जनहित के प्रति रहे समर्पित,
शासन तथा प्रशासन सारा।

खुशियों से हो भरा राष्ट्र यह,
गुंजित हो 'जयहिंद' सुनारा।
बढ़ें सुपथ पर मिलकर सारे
राष्ट्र बने प्राणों से प्यारा।
ऐसा हो गणतंत्र हमारा॥

देशभक्ति की धार सुपावन,
जन–मन में हो पुनः प्रवाहित।
युवक हमारे निकलें, निर्भय,
प्राण हथेली पर लें, परहित।

आतंकों के, उग्रवाद के
हामी सारे करें किनारा।
ऐसा हो गणतंत्र हमारा॥

भ्रष्टाचार रहित हो शासन,
कर्मी सारे बने हितैषी।
जगे हमारे अंतर्मन में,
निश्छलता से भाव स्वदेशी।

कभी न मानव बने यहाँ का
मानवता का ही हत्यारा।
ऐसा हो गणतंत्र हमारा॥

समता–समरसता–समृद्धि का,
हो कण–कण में नव संचारण।
सभी समस्याओं का हो फिर,
आज राष्ट्रहित, शीघ्र निवारण।

निर्बलतम जो भारत जन हैं
उनको भी अब मिले सहारा।
ऐसा हो गणतंत्र हमारा॥

भीष्म–भीम व पार्थ सदृश हों,
वीर–जयी, सेनानी सारे।
अपराजित हो सैन्य वाहिनी,
विश्व–विजय के हित हुंकारे।

पथ प्रशस्त करें वसुधा का
जय ध्वज वाहक भारत न्यारा।
ऐसा हो गणतंत्र हमारा॥

आज 26 जनवरी है। हमारा 61वां गणतंत्र दिवस। लेकिन यह बात हमें ही नहीं, बहुतों को सालती होगी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय दिवसों को होली-दिवाली-ईद की तरह क्यों नहीं मनाया जाता इन राष्ट्रीय दिवसों को लोग उन त्यौहारों की तरह क्यों नहीं मनाते, जिनसे पूरा समाज और उसकी इकाई यानी कि हर व्यक्ति जुडता सा प्रतीत होता है महीने भर पहले से जो उत्साह आम जनता के स्तर पर सामाजिक और सामुदायिक त्यौहारों के प्रति दिखता है वो पहल, लगाव, अपनत्व और जिजीविषा इन राष्ट्रीय दिवसों के प्रति क्यों नहीं ऐसा क्यों है कि ये राष्ट्रीय दिवस 365 दिनों में बस एक दिन आकर चले जाते हैं हम इनके साथ सामाजिक स्तर पर वैसा तादात्म्य क्यों नहीं स्थापित कर पाते, जैसा कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, बिहार-उत्तर प्रदेश में सूर्य पूजा या छठ, मकर संक्रांति, पंजाब में लोहडी और दक्षिण में पोंगल के साथ रिश्तों की आम लेकिन सघन बुनावट देखने को मिलती है दिलचस्प है कि ये सभी सामाजिक-सांस्कृतिक त्यौहार भी जनता के स्तर पर रचे-बसे हैं, जिनमें क्षेत्रीय स्तरों पर आम शिरकत भी जबर्दस्त होती है, लेकिन हमारा गणतंत्र, जो याद दिलाता है कि आज के ही दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसकी प्रस्तावना का वाक्य ही 'हम भारत के लोग... से शुरू होता है, जिसे जनता के दम पर ही गणतंत्र या रिपब्लिक कहा जाता है, उसके प्रतीक दिवस पर जनसंवेदना में ऐसा अंतर क्यों तो क्या हमारी राष्ट्रीय चेतना कहीं कमजोर हो रही है... ऐसे अनेक सवाल जेहन में उठने स्वाभाविक हैं। माना कि राजधानी दिल्ली में आकर्षक परेड होती है। पूरे राष्ट्र की बहुलवादी लोकतांत्रिक संस्कृति की झांकी भी राजपथ पर जुलूस की शक्ल में दिखती है। देश की सैन्य शक्ति का भी भव्य प्रदर्शन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी मेहमानों समेत सभी अतिविशिष्ट लोग इस सरकारी कार्यक्रम में शरीक होते हैं। थोडा संक्षिप्त लेकिन इसी तर्ज पर प्रदेश की राजधानियों में भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं। देश भर के स्कूलों में भी पारंपरिक परेड होती है, जहां बच्चों को शामिल किया जाता है। लेकिन ये सब होता है बस कुछ घंटे के लिए ही, आम जनता के स्तर पर क्या होता है खेत-खलिहान, सडक-पगडंडी, बाजार-चौराहों पर जहां दिवाली के पटाखे फूटते हैं, होली के रंग चलते हैं, गुलाल उड़ता है, फाग छिड़ती है, ईद में गले मिलते हैं, जन्माष्टमी में हांडी फूटती है, दशहरे पर अनगिनत जगह रावण मरता है - वहां सन्नाटा क्यों है, राष्ट्रीय जश्न मनाने में जनता परहेज करती सी क्यों लगती है कहीं रिपब्लिक डे में 'पब्लिक' और गणतंत्र दिवस में 'गण' पीछे तो नहीं छूट रहा

ऐसे सवालों का जेहन में उठना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि देश-समाज बदल रहा है। बाजार का वैश्विक दौर है। दुनिया छोटी होकर गांव की शक्ल ले रही है। लेकिन क्षेत्रीय संदर्भ अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर सजग हैं। वे समाज, राजनीति, संस्कृति, विकास सभी स्तरों पर नई करवट ले रहे हैं। तो क्या वैश्विकता और क्षेत्रीयता के बीच राष्ट्रीय संदर्भ का ताप कम हो रहा है यह मुद्दा बहस का विषय हो सकता है लेकिन एक वास्तविकता ये तो है ही कि गांधी-नेहरू की रहनुमाई में आमजन के संघर्ष की आग में तपे-बढ़े आजादी के आंदोलन के मूल्यों-संस्कारों के आधुनिक संदर्भ और परिवेश बदल रहे हैं। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि आज न तो कोई ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और न ही कोई ऐसा राष्ट्रीय अखबार जिसकी धमक पूरे देश में महसूस की जाती हो - ये बापू का जमाना नहीं है जो किसी आश्रम से भी चंद पंक्तियां लिखकर पूरे देश को एकजुट कर सकते थे। इस बदलते परिदृश्य में जब युवाओं की लगभग आधी से ज्यादा आबादी वाला 'युवा भारत' आने वाले समय में 'महाशक्ति' बनने को तैयार है, हमें अपनी राष्ट्रीय धरोहर, जडों से भटकने की प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि यही लोकतांत्रिक-बहुलवादी संस्कृति ही हमारी राष्ट्रीय पूंजी है, चेतना है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक भले ही आज 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हों, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में डेढ़ हजार से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, लगभग साढ़े छह हजार जातियां हैं, ढाई दर्जन प्रमुख त्यौहार हैं - और इन सभी विभिन्नताओं के बीच हम एक हैं। यही अनेकता में एकता हमारी ताकत है, थाती है।

इन विभिन्नताओं के बीच हमारी एकजुटता जहां हमारी पूंजी है, वहीं ये विभिन्नताएं हमारी खूबसूरती। यही हमारे हिंदुस्तानी गुलदस्ते के हर फूल की अलग महक और विशिष्ट पहचान भी। आज जरूरत है बेहतर समन्वय और समग्र दृष्टिबोध की। एक खास बात यह भी है कि हमारे सभी सामाजिक त्यौहारों का एक सांस्कृतिक-पौराणिक संदर्भ है जो कहीं न कहीं व्यापक संदर्भों में आधुनिकता से भी जुड़ता है। ठीक इसी तरह हमारी आधुनिक लोकतांत्रिक-गणतंत्रीय सोच को भी भारत की हजारों साल की मध्यमार्गी जनतंत्रीय दृष्टि से जोड़ने की जरूरत है। साथ ही सरकार के समानांतर आमजन के स्तर पर राष्ट्रीय दिवसों को मनाने की पहल होनी चाहिए, भले ही ऐसे प्रयास छोटे ही क्यों न हों। इससे हमारे राष्ट्रीय दिवस ही नहीं, सारा राष्ट्रीय कलेवर और भी ज्यादा गणतंत्रीय मूल्यों-संस्कारों-सरोकारों से संपन्न हो सकेगा। क्षेत्रीय ताने-बाने और वैश्विकता के ध्रुवों के बेहतर जुड़ाव का माध्यम हमारी राष्ट्रीय चेतना और भारत के वे सांस्कृतिक मूल्य ही हो सकते हैं - जो गांधी के तीन शब्द 'करो या मरो' से पूरे देश को एकजुट कर देते हैं, तिलक के गणेशोत्सव कार्यक्रम नवसांस्कृतिक आभा का संचार करते हैं और शिकागो के मंच पर विवेकानंद 'भाइयों और बहनों' संबोधन के बाद सारी दुनिया को वेदांत के संदेश से चमत्कृत और मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो ये है हमारी ताकत, जिसे कोई सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातीय, विभाजनकारी या कोई दकियानूसी ताकत कभी तोड़ नहीं सकती। यही हमारी हजारों साल की पूंजी 'आध्यात्मिक शक्ति' भी है, जिसे खुद को साबित करने के लिए किसी लाल चौक पर झंडा फहरा कर कोई अग्निपरीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये वो राष्ट्रीयता है जो लाल किले की प्राचीर से भी उतनी ही सहजता से प्रकट होती है, जितनी किसी सुदूर अंचल के खेत-खलिहान या पगडंडी से। बस इस शाश्वत भावना को फिर से पुनर्जीवित और आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी हम हर उस धुंधलके को मिटा पाने में सफल होंगे, जो यदाकदा प्रश्नचिह्न बन के हमारे राष्ट्रीय मानस को कुरेदने की चेष्टा करते हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुंद्रक – नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड़, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-बी, फेस-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गंग्याल, जम्मू से मुद्रित। संपादक– नीलम सिंह गिल। फोन नंबर : (95) 191-2574109, 2548103 RNI Regd. No: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

एपीएस दमाना में रेबीज जागरूकता पर शिक्षाप्रद सत्र आयोजित किया

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। विद्यांजलि स्कूल वालंटियर प्रोग्राम और विज्ञान सेतु फाउंडेशन के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल, एपीएस दमाना ने सरकारी मिडिल स्कूल परवाह के छात्रों के लिए - रेबीज- इसके कारण और प्रबंधन - पर एक प्रभावशाली और जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। स्कूल की प्रिंसिपल पुष्पिंदर कौर के नेतृत्व में आयोजित इस सत्र का उद्देश्य रेबीज के कारणों, रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

कौर ने बताया कि रेबीज एक वायरल बीमारी है जो मनुष्यों सहित स्तनधारियों के तंत्रिका तंत्र को लक्षित करती है और मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंच के माध्यम से लार के माध्यम से फैलती है। इस सत्र में प्रारंभिक पहचान, टीकाकरण, जिम्मेदार पालतू जानवरों की देखभाल और संपर्क के बाद तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व जैसे विषयों को शामिल किया गया। छात्रों ने हाइड्रोफोबिया, चिंता, मनुष्यों में तंत्रिका संबंधी उत्तेजना और पागल जानवरों में व्यवहार संबंधी परिवर्तनों जैसे हॉलमार्क लक्षणों के बारे में सीखा। सभा को संबोधित करते हुए कौर ने सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने में ऐसे जागरूकता सत्रों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को स्वास्थ्य राजदूत के रूप में कार्य करने और अपने समुदायों में रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सत्र में एपीएस दमाना और जीएमएस परवाह के कक्षा पांच के छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की जिन्होंने उत्साहपूर्वक चर्चा में भाग लिया और गतिशील प्रश्नोत्तर खंड के दौरान स्पष्टीकरण मांगा।

जीजीएम साइंस कॉलेज में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। जीजीएम साइंस कॉलेज की एनएसएस इकाई ने - मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा - थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करने और छात्रों के बीच नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में सक्रिय मतदाता भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना था। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) रोमेश कुमार गुप्ता के उद्घाटन भाषण से हुई जिन्होंने लोकतांत्रिक जागरूकता और प्रथाओं को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने युवा नागरिकों को देश के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मतदान की अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राहुल कैत ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका पर एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने चुनाव आयोग की संरचना और चुनावी अखंडता को बनाए रखने के उसके प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही राजनीति में धनबल, जातिवाद और आपराधिक प्रभावों जैसी प्रमुख चुनौतियों पर भी बात की। उनके व्याख्यान ने छात्रों को सूचित और नैतिक मतदान के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।

सीयू जम्मू ने गरुड़ एयरोस्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग ने इसरो भवन, सीयू जम्मू में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया। कुलपति प्रो. संजीव जैन के नेतृत्व में जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय और गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. यशवंत सिंह, गरुड़ एयरोस्पेस के मुख्य परिचालन अधिकारी डॉ. विजय कुमार, ईसीई के विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार झा, संकाय सदस्य, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित थे।

प्रो. यशवंत सिंह ने जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उपलब्ध बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने उद्योग 5.0 के अनुसार समाज एवं राष्ट्र के लिए समाधान विकसित करने के लिए ऐसे समझौता ज्ञापन एवं सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। गरुड़ एयरोस्पेस के मुख्य परिचालन अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में ड्रोन तकनीक पर अपना उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई। सीओई का उद्देश्य छात्रों को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रदान करना, यूएवी लैब विकसित करना और कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए समाधान विकसित करने के लिए जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में ड्रोन तकनीक पर अनुसंधान और विकास सुविधा विकसित करना है। कार्यक्रम का समन्वय सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र (एसडीसीएसएस) के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुनील दत्त शर्मा और रिसर्च एसोसिएट डॉ. हनीत कौर ने किया।

राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर अखनूर में आयोजित किया हेरिटेज वॉक

अखनूर 25 जनवरी (हि.स.)। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सरकार की आयुक्त सचिव याशा मुद्गल, आईएएस के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों ने जम्मू की समृद्ध, सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया और सतत पर्यटनए, नागरिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया।

दिन का मुख्य आकर्षण जम्मू पर्यटन निदेशालय द्वारा आयोजित एक हेरिटेज वॉक था जो अखनूर के निकट चेनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल अम्बारां से शुरू हुआ।

प्रतिभागियों ने इस वॉक के दौरान कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया जिनमें टीआरसी अखनूर गुरुद्वारा बाबा सुंदर सिंह जी, परशुराम मंदिर, पांडव गुफा, अखनूर किला, दुर्गा मंदिर और जिया पोता घाट शामिल हैं। जिया पोता घाट ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं 17 जून 1822 को महाराजा रणजीत सिंह ने श्री गुलाब सिंह का राज्याभिषेक किया था।

जम्मू के पर्यटन निदेशक विकास गुप्ताए, जेकेएएस ने पर्यटन को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हेरिटेज वॉक जैसे कार्यक्रम लोगों को जम्मू के समृद्ध इतिहास से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को नियमित रूप से आयोजित करने पर जोर दिया जिससे विद्यार्थियों को न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर की गहरी समझ हो बल्कि समावेशिता, स्थिरता और सांस्कृतिक संपत्तियों को संरक्षित व बढ़ावा देने की जिम्मेदारी का भी एहसास हो।

इस बार 29 जनवरी बुधवार को आ रही है मौनी अमावस्या

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी का शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक है। मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत है। वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है,पर धर्मग्रंथों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है,अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव है,माघ (मौनी) अमावस्या के विषय में श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस वर्ष माघ अमावस्या तिथि 28 जनवरी मंगलवार शाम 07 बजकर 37 पर शरू होगी और 29 जनवरी बुधवार शाम 06 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी माघ अमावस्या तिथि 29 जनवरी को है इसलिए इस वर्ष माघ (मौनी) मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को होगी।

जंगली सूअर के हमले में सात लोग घायल

पुंछ 25 जनवरी (हि.स.)। पुंछ जिले की मंडी तहसील में जंगली सूअर के हमले में सात लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम को सूचना मिली कि गली पिंडी ब्लॉक साथरा के इलाके में एक जंगली सूअर ने स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया जिसमें सात लोग मामूली रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा में ले जाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वन्यजीव अधिकारियों को गांव में बुलाया गया है।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी

अखनूर 25 जनवरी (हि.स.)। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को भारतीय सेना के टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड अखनूर जम्मू में स्थित अखनूर हेरिटेज म्यूजियम में आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी में 500 से अधिक छात्रों, शोधकर्ताओं और आगंतुकों ने दौरा किया। यह म्यूजियम 14 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था। इस म्यूजियम में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और सैन्य इतिहास को प्रदर्शित किया गया है।

इस भ्रमण का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गर्व जागृत करना और उन्हें भारत की धरोहर से परिचित कराना था। इसमें विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की।

केपी के कश्मीर में सुरक्षित वापसी से पहले मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग की

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार से कश्मीरी हिंदू समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए कश्मीर में मंदिरों और मंदिर संपत्तियों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। त्रिकुटा नगर में भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने डॉ. ताहिर चौधरी, बलबीर राम रतन और डॉ. प्रदीप महोत्रा ??के साथ एनसी सरकार की आलोचना की जिन्होंने अतीत में वादे किए थे लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। एडवोकेट सुनील सेठी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने के बाद से कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, उन्हें बेच दिया गया या उन्हें पट्टे पर दे दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीरी हिंदू समुदाय तभी वापस लौटने में सुरक्षित महसूस करेगा जब इन पवित्र स्थानों को बहाल किया जाएगा और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्वागत योग्य, सुरक्षित वातावरण बनाया जाएगा। सेठी ने कहा नेकां सरकार को सत्ता में आए तीन महीने से ज्यादा हो गए हैं फिर भी कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति, अधिमानतः एक सर्वदलीय या मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि समिति को आतंकवाद के कारण नष्ट किए गए मंदिरों, अवैध रूप से कब्ज़े वाली मंदिर संपत्तियों और दबाव में बेची या पट्टे पर दी गई संपत्तियों की व्यापक सूची बनानी चाहिए।

नटरंग ने मतदाता दिवस पर लोकतंत्र का असली मंत्र का मंचन किया

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नटरंग थिएटर ग्रुप ने जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, जम्मू में हिंदी नाटक लोकतंत्र का असली मंत्र का मंचन किया। बलवंत ठाकुर द्वारा लिखित और नीरज कांत द्वारा निर्देशित यह नाटक मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जम्मू-कश्मीर के तत्वावधान में प्रस्तुत किया गया जिसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में बी.आर. शर्मा (सेवानिवृत्त आईएएस), राज्य चुनाव आयुक्त; शालीन काबरा, वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव); रोमेश कुमार (आईएएस), संभागीय आयुक्त, जम्मू; शाहिद इकबाल चौधरी, प्रशासनिक सचिव, योजना, विकास और निगरानी विभाग; और सचिन कुमार, उपायुक्त, जम्मू शामिल थे।

यह नाटक एक सम्मोहक नाट्य प्रस्तुति है जिसे नागरिकों को उनके वोट की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में मतदान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है और लोगों से राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के लिए अपनी चुनावी ज़िम्मेदारी को अपनाने का आग्रह करता है। कहानी भ्रष्टाचार, बेईमानी और प्रणालीगत अक्षमताओं की चुनौतियों से जूझ रहे निराश युवाओं के चित्रण के साथ शुरू होती है। उनके गुस्से और निराशा का सामना एक शिक्षित चरित्र द्वारा एक विचारोत्तेजक प्रश्न से किया जाता है- आप स्थिति को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न युवाओं को अपनी उदासीनता का सामना करने और सुधार के लिए एक शांतिपूर्ण और प्रभावी उपकरण के रूप में मतदान की क्षमता का एहसास करने के लिए मजबूर करता है। नाटक मतदान के प्रति विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों को दर्शाने के लिए व्यंग्य का उपयोग करता है। विभिन्न आयु समूहों और सामाजिक स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र बहाने और गलत धारणाओं को प्रकट करते हैं जो चुनावी भागीदारी में बाधा डालते हैं। इन दृष्टिकोणों को उजागर करके नाटक उदासीनता के खतरों और नागरिकों द्वारा अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य की उपेक्षा करने पर खोए अवसरों को रेखांकित करता है। अपनी आकर्षक कहानी और दमदार अभिनय के ज़रिए लोकतंत्र का असली मंत्र दर्शकों को मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए प्रेरित करता है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि मतदान लोकतंत्र में अंतिम शक्ति है, जो परिवर्तनकारी बदलाव लाने में सक्षम है। कार्यक्रम का समापन सभी नागरिकों से यह सुनिश्चित करने की जोरदार अपील के साथ हुआ कि हर वोट मायने रखता है जिससे एक मज़बूत और ज़्यादा जीवंत लोकतंत्र के लिए सामूहिक भागीदारी के महत्व पर बल मिलता है।

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक इकाइयों की भयावह स्थिति पर गंभीर चिंता जताई

जम्मू 25 जनवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक इकाइयों की भयावह स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। इस बीच उन्होंने मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र के प्रति उदासीन रवैये के लिए लगातार सरकारों को जिम्मेदार भी ठहराया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा जम्मू,कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास योजना को बढ़ाने के आश्वासन के बारे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रतन लाल गुप्ता ने कहा कि संघर्षरत औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले दस वर्षों में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने दुख जताया कि सरकार बड़े,बड़े दावे कर रही है लेकिन समर्थन और उचित नीति ढांचे की कमी के कारण उद्योगपतियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू में औद्योगिक क्षेत्र गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिसमें कई इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और अन्य बंद होने के कगार पर हैं।

किश्तवाड़ में सैनिक स्कूल कोचिंग कार्यक्रम पूरा किया

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में भारतीय सेना ने किश्तवाड़ जिले के भंडारकुट में दो महीने का सैनिक और सैन्य स्कूल प्रवेश कोचिंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित यह पहल पिछले साल 19 नवंबर को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षाओं के लिए इच्छुक छात्रों को तैयार करना था।

इस कार्यक्रम में 50 छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखी गई जिसमे कक्षा 6वीं के लिए 32 और कक्षा 9वीं के लिए 18 बच्चों ने भाग लिया। उन्हें प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए केंद्रित कोचिंग, अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस पहल ने सुनिश्चित किया कि ग्रामीण युवाओं को ऐसे संसाधनों और ज्ञान से लैस किया जाए जो दूरदराज के क्षेत्रों में अक्सर दुर्गम अवसरों को भुनाने के लिए उपलब्ध हों। इस प्रयास के माध्यम से भारतीय सेना ने शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। माता-पिता ने सेना द्वारा उनके घर तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सहायता पहुंचाने के प्रयासों के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। इस पहल से भंडारकुट और आस-पास के क्षेत्रों में युवा दिमागों को अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने और सेवा और उत्कृष्टता के करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है, जिससे देश की प्रगति में योगदान मिलेगा

प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने संविधान गौरव अभियान पहल के तहत आयोजित प्रश्नोत्तरी और ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए त्रिकुटा नगर स्थित अपने मुख्यालय में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

बहुविकल्पीय प्रारूप में आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर सत शर्मा, महासचिव अशोक कौल, विधायक युद्धवीर सेठी, विधायक अरविंद गुप्ता और भाजपा एनईएम प्रिया सेठी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में बोलते हुए सत शर्मा ने विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी और भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया जो सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की गारंटी देता है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को मिटाने और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर की भी प्रशंसा की।

इसी बीच प्रिया सेठी ने भारतीय संविधान के महत्व और अन्य देशों के संविधानों की तुलना में इसके अद्वितीय दृष्टिकोण पर विस्तार से बताया। उन्होंने प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी और उन्हें संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता कृषक शर्मा और राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी अनामिका खजूरिया सहित विशेष अतिथि भी शामिल हुए।

राजीव कुमार ने 50 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया

जम्मू 25 जनवरी (हि.स.)। बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ. राजीव कुमार भगत ने चक अवतारा पंचायत घर से लिंक रोड पल्ली रत्नाल रोड से कैलाश हायर सेकेंडरी स्कूल चक मुरार तक मोटी इंटरलॉकिंग टाइलों के माध्यम से लिंक रोड के निर्माण कार्य तथा बाल कृष्ण के घर से गांव चक मुरार में जीत राज तक 50 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये कार्य यूटी सेक्टर के तहत पीडब्ल्यूडी आरएंडबी विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। डॉ. राजीव कुमार भगत ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत सैदगढ़ में 33 लाख रुपये, पंचायत चक मुरार में 23 लाख रुपये तथा पंचायत नौग्रां में 23 लाख रुपये कुल 79 लाख रुपये की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिलाई कोर्स शुरू किया

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। दूरदराज के इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने मिशन को जारी रखते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत थात्री के फागसू गांव की महिलाओं के लिए 30 दिवसीय सिलाई और सिलाई कोर्स का उद्घाटन किया। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिकता वाले घरों और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए व्यावहारिक कौशल और अवसर प्रदान करना है।

इस पहल में आठ महिलाएं शामिल हैं जिसमें भारतीय सेना द्वारा सिलाई मशीन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। इस परियोजना को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिससे प्रतिभागी चुनौतीपूर्ण समय के दौरान खुद का और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए भारतीय सेना के एक प्रतिनिधि ने क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए गरीबी और भूख को दूर करने में ऐसी पहलों के महत्व पर जोर दिया। यह परियोजना वंचित समुदायों के उत्थान और महिलाओं को उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए सेना के समर्पण को दर्शाती है।

कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम फागसू की महिलाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों को एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर विशेष व्याख्यान का आयोजन

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने रियासी जिले के चसाना के सुदूर क्षेत्र में एक प्रेरक व्याख्यान का आयोजन किया जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास में शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर देना था। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।

इस सत्र में लड़कियों की शिक्षा और समावेशी शिक्षण वातावरण के निर्माण पर विशेष जोर देते हुए दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने में साक्षरता, कौशल निर्माण और ज्ञान साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भारतीय सेना के जवानों ने स्थानीय शिक्षकों के सहयोग से युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के मार्ग के रूप में शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रेरक व्याख्यान दिए।सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा शिक्षा प्रगति की आधारशिला है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

पुंछ में धूमधाम से मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस

जम्मू, 25 जनवरी (हि.स.)। हाल ही में पुंछ जिले के कलाली, महल स्थित सरकारी हाई स्कूल में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। कार्यक्रम में लड़कियों के सशक्तिकरण और अधिकारों पर जोर दिया गया और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यक्तिगत सुरक्षा तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम में 20 लड़कियों, 15 लड़कों और 2 शिक्षकों सहित 37 व्यक्तियों ने भाग लिया। लड़कियों के सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ आयोजित की गईं जिसमें एक ऐसे समाज के निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया जहाँ लड़कियों को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है व उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का अवसर दिया जाता है।

इस कार्यक्रम का मुख्य विषय लड़कियों के अधिकारों और सशक्तिकरण की वकालत करने की सामूहिक प्रतिज्ञा थी जो जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए समान अवसरों के महत्व को पुष्ट करती है। भारतीय सेना ने छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए स्टेशनरी और शैक्षिक सामग्री

वितरित की जिससे सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिला। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा लड़कियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना एक प्रगतिशील समाज के निर्माण का अभिन्न अंग है। हम स्थानीय समुदायों का समर्थन करने और लड़कियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं खासकर दूरदराज के इलाकों में। प्रतिभागियों ने सेना की पहल के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर में कैंसर संकट

जम्मू-कश्मीर में कैंसर के मामलों में खतरनाक वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है, फिर भी सरकार ने इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। हर साल 12,000 से ज़्यादा नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और हर साल 10-12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, स्थिति और भी खराब होती जा रही है। सिर्फ़ 2019 और 2022 के बीच ही 51,500 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए और 2024 में SKIMS सौरा, GMC श्रीनगर और GMC जम्मू जैसे बड़े अस्पतालों में हज़ारों नए मामले दर्ज किए गए। इसके बावजूद, कैंसर के इलाज की सुविधाओं के मामले में यह क्षेत्र गंभीर रूप से कमज़ोर बना हुआ है, जिसकी वजह से मरीज़ों को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में महंगी चिकित्सा सेवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे न सिर्फ़ उनके वित्तीय संसाधन खत्म होते हैं, बल्कि पहले से ही विनाशकारी स्थिति में उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव भी होता है।

हालाँकि, लगातार सरकारों को स्वास्थ्य सेवा विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज और केंद्रीय निधियाँ मिली हैं, लेकिन कुप्रबंधन और खराब योजना के कारण चिकित्सा बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त हो गया है। जम्मू-कश्मीर में कैंसर के मरीज़ों को विशेष ऑन्कोलॉजी सेंटर, उन्नत डायग्नोस्टिक टूल और किफ़ायती उपचार विकल्पों की कमी के कारण लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई 2024 में गरीबों के लिए कैंसर उपचार और प्रबंधन निधि को बंद कर दिए जाने से संकट और भी बढ़ गया है, जिससे हज़ारों आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज़ों को कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी जीवन रक्षक चिकित्सा के लिए कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। कई परिवार अब या तो इलाज छोड़ने या कर्ज में डूबने को मजबूर हैं, जो इस गंभीर मुद्दे के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

हालाँकि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा (H&ME) विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (SCI) की स्थापना के लिए 10.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन यह पहल पर्याप्त नहीं है। कैंसर के मामलों की विशाल संख्या के कारण पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ कई पूरी तरह कार्यात्मक कैंसर उपचार केंद्रों की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं में तेज़ी लाने में विफल रहने में सरकार की लापरवाही इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने में तत्परता की कमी को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार का दावा किया है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया है, जो साबित करता है कि जहां इच्छा है, वहां कोई रास्ता है। हालांकि, कैंसर के इलाज की बात करें तो यही प्रतिबद्धता गायब है। यह चौंकाने वाला है कि वित्तीय सहायता और नीतिगत घोषणाओं के वर्षों के बाद भी, जम्मू-कश्मीर में रोगियों को अभी भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण ऑन्कोलॉजी देखभाल तक पहुंच नहीं है। समय की मांग तत्काल हस्तक्षेप है। सरकार को जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में अच्छी तरह से सुसज्जित कैंसर उपचार सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, गरीब कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता की बहाली आगे की परेशानी और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कैंसर एक ऐसी लड़ाई है जिसे समय पर निदान, उचित उपचार और वित्तीय सहायता से जीता जा सकता है। दुर्भाग्य से, सरकार की निष्क्रियता इसे जम्मू-कश्मीर में कई लोगों के लिए हारने वाली लड़ाई बना रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे तय करेंगे आआपा का भविष्य

मनोज कुमार मिश्र

50 फरवरी, 2025 को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 08 फरवरी, 2025 को घोषित होंगे। केवल इस विधानसभा चुनाव में अगर जीत न मिल पाई तो आम आदमी पार्टी (आआपा) का बिखरना तय माना जा रहा है। चुनाव में तो वैसे अनेक दल अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं लेकिन चुनाव आआपा, भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। अपने 13 साल के राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे आआपा के सर्वेसर्वा और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर है। शराब घोटाले में छह महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। संभावित हार से आशंकित केजरीवाल हर रोज कोई न कोई घोषणा करके चुनावी बाजी पलटने में लगे हुए हैं। उनके कट्टर ईमानदार की छवि को शराब घोटाले से अधिक शीशमहल (मुख्यमंत्री की सरकारी कोठी पर करोड़ों खर्च करके महल बनाने का मामला) कांड ने खराब कर दिया है। कैग (सीएजी) रिपोर्ट ने उनके और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करके उनको महाभ्रष्ट साबित कर दिया। उस रिपोर्ट को विधानसभा में न पेश करके उन्होंने अपनी खूब बेइज्जती करवाई।

जिसे आम लोग कहते थे वही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कह दिया। वे आआपा को आप-दा कहने लगे हैं और उनका कहना है कि हार को टालने के लिए केजरीवाल रोज कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं।

1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा इस बार पूरे दमखम से सत्ता पाने के लिए लगी हुई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर देशभर के बड़े भाजपा नेता, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री व नेता दिल्ली में सभा कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। हर सीट पर भाजपा ने कई स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। गुटबाजी टालने के लिए भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ना तय किया है। चुनाव की घोषणा थोड़े ही दिन पहले हुई लेकिन भाजपा तो काफी समय से केजरीवाल और उनकी टीम का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। इस बार सोशल मीडिया पर भी भाजपा आआपा से काफी आगे है। आआपा के सर्वेसर्वा केजरीवाल ने खुद पार्टी में शुरू से जुड़े अनेक बुद्धिजीवियों को पार्टी से अलग करके अपने हाथ काट लिए। अब उनका बचाव करने वाले बेहद नौसीखिए हैं जो रटा रटाया बयान दोहराकर अपनी और अपनी पार्टी की जगहंसाई करवा रहे हैं।

सालों दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस साल 2013 यानी आआपा के वजूद में आने के बाद से लगातार हाशिए पर पहुंचती जा रही है। लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित 2013 का विधानसभा चुनाव न केवल खुद हारी बल्कि कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट और केवल आठ सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे कोई सीट नहीं मिली और उसका वोट औसत घटकर 9.71 फीसद रह गया। इतना ही नहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 4.26 फीसद वोट मिले। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आआपा से सीटों का तालमेल था। सात में से तीन सीटों पर कांग्रेस और चार पर आआपा लड़ी। चुनाव में सभी सातों सीटें भाजपा लगातार तीसरी बार जीती। कांग्रेस को 18.50 फीसद वोट मिले। कांग्रेस के ताकतवर हो जाने के डर से इस चुनाव में आआपा ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ना तय किया।

कांग्रेस ने अपने मूल वोटर-अल्पसंख्यक, दलित और पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मूल निवासी) के लोगों का समर्थन पाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में मुस्लिम आबादी अब 12 से बढ़ कर 15 फीसद से ज्यादा हो गई है। 70 में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20 फीसद से ज्यादा हैं। इनमें सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमरान, ओखला, मुस्तफाबाद, किराड़ी, चांदनी चौक, गांधीनगर, करावल नगर, विकास पुरी, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर, बाबरपुर, मोतीनगर, मालवीय नगर, सीमापुरी और छत्तरपुर शामिल हैं। उनपर कांग्रेस के न केवल उम्मीदवार मजबूत हैं बल्कि कांग्रेस पूरी ताकत से लगी है।

इसी तरह 12 अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। दलितों में कांग्रेस का कुछ असर अब भी बचा है। उन इलाकों में कांग्रेस की सभा में भीड़ जुट रही है। पूर्वांचल के प्रवासी दिल्ली में सालों कांग्रेस का साथ देकर उसे सत्ता दिलाते रहे। दिल्ली के 70 में से 42 सीटों पर पूरबियों (पूर्वांचल के प्रवासी) का वोट 20 फीसद से ज्यादा है।

यह तीनों और दिल्ली के गांव का एक वर्ग अगर कांग्रेस से जुड़ जाए तो उसके पुराने दिन लौट आ जाएंगे। कांग्रेस इस चुनाव में धन-बल से इस प्रयास में लगी है। कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी दिल्ली के अल्पसंख्यक इलाकों से जनसभा की शुरुआत कर चुके हैं।कांग्रेस यह संदेश देने में लगी है कि वही देशभर में भाजपा से लड़ रही है। 2022 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को सात अल्पसंख्यक सीटों पर जीत दिला कर यह संदेश पहले ही दे दिया था। इसी भरोसे 2013 के चुनाव में कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का साथ मिला तो उसके वोट औसत बढ़ गए और साथ छोड़ा तो कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजसेवी अण्णा हजारे के आंदोलन में शामिल अनेक लोगों ने 26 अक्तूबर, 2012 को आआपा के नाम से राजनीतिक दल बनाकर 2013 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना तय किया। वैसे अण्णा हजारे ने राजनीतिक पार्टी बनाने का विरोध किया था। पहले ही चुनाव में ही बिजली-पानी फ्री का मुद्दा कारगर हुआ। आआपा को 70 सदस्यों वाले विधानसभा में करीब 30 फीसद वोट और 28 सीटें मिली। भाजपा करीब 34 फीसद वोट के साथ 32 सीटें जीती। दिल्ली में 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट के साथ केवल आठ सीटें मिली। माना गया कि दिल्ली का अल्पसंख्यक भाजपा को हराने वाले दल का सही अनुमान लगाए बिना कांग्रेस को वोट दिया था। अगले चुनाव में अल्पसंख्यक आआपा से जुड़ गए तो कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई।

कांग्रेस की कमजोरी और भाजपा की अधूरी तैयारी के चलते और बिजली-पानी फ्री के वायदे ने आआपा को 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में रिकार्ड 54 फीसदी वोट के साथ 67 सीटों पर जीत दिलवा दी। उस चुनाव ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस कोई सीट नहीं मिली और उसका वोट औसत घट कर 9.7 पर आ गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आआपा को फिर से भारी जीत मिली। उसे 70 में से 62 सीटें मिली। फिर तो आआपा पंजाब में भी विधानसभा चुनाव जीत कर सरकार बना ली और अखिल भारतीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। इतना ही नहीं वह जगह-जगह कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करने लगी। इस दौरान विभिन्न आरोपों में एक-एक करके आआपा नेताओं की गिरफ्तारी और शराब घोटाले की आंच पार्टी के प्रमुख केजरीवाल तक पहुंचने, उनकी गिरफ्तारी आदि ने आआपा की साख को बट्टा लगा दिया। इस चुनाव में तो आआपा को हराने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां घोषित करने में आआपा से आगे कांग्रेस और भाजपा निकल गई। भाजपा ने तो किश्तों में घोषणा (संकल्प) पत्र जारी किया और यह अभी जारी है। कांग्रेस भी आआपा से एक कदम आगे बढ़ कर घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। आआपा को उसी के मुद्दे पर विरोधी दलों ने बुरी तरह से घेर दिया है। आआपा के लिए बचाव का रास्ता कम बचा है। आआपा के पक्ष में बोलने वाले बड़े नेताओं की तादाद लगातार घट रही है। कुछ को केजरीवाल ने पार्टी से अलग किया और कुछ खुद उनके व्यवहार से बाहर हो गए।

जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत देते हुए उन्हें दफ्तर न जाने, सरकारी फाइल न देखने आदि की हिदायत दी तब मुख्यमंत्री पद छोड़कर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। वह पहले दिन से अपने को केयरटेकर बताने में लगी हुई हैं। जिस भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर राजनीति शुरू की, उसी भ्रष्टाचार में चारों तरफ से घिर गए। जो काम वे और उनकी पार्टी के लोग गिना रहे हैं, उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। खुद केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई न कर पाने, हर घर को साफ पानी न दे पाने और दिल्ली की सड़कों को न ठीक करवाने के लिए माफी मांग ली। उनके काम के दावों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। कहने के लिए आआपा अब राष्ट्रीय पार्टी है। पंजाब में उसकी सरकार है लेकिन दिल्ली हारते ही केजरीवाल पस्त हो जाएंगे। यह पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल की पार्टी है। उसके बाद पार्टी को बिखरते देर नहीं लगेगी।

चुनाव प्रचार के दौरान जो दिल्ली का माहौल लग रहा है, उससे यही लग रहा है कि भले कांग्रेस मुख्य मुकाबले में न आ पाए लेकिन इतने वोट पा जाएगी कि आआपा के वोट औसत में भारी गिरावट होगी। इसका लाभ सीधे भाजपा को मिलना तय है। अगर मतदान तक हालात नहीं बदले तो इस बार दिल्ली की सरकार से आआपा दूर हो सकती है। सभाओं के हिसाब से भी ज्यादा भीड़ भाजपा के नेता जुटा रहे हैं। हड़बड़ी में आआपा नेता अरविंद केजरीवाल गलतबयानी कर रहे हैं। रामायण प्रकरण पर उनकी टिप्पणी से उनकी खूब जगहंसाई हुई। हर रोज चुनाव प्रचार तीखा होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में घटिया निजी आरोप लग रहे हैं। भाजपा लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और आआपा हार से बचने के लिए कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है लेकिन यह चुनाव आआपा नेता के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव बन गया है।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकारी संपादक हैं।)

आखिर कब समझेंगे हम गणतंत्र की मूल भावना

- योगेश कुमार गोयल

प्रतिवर्ष की भांति एक और गणतंत्र दिवस हमारी चौखट पर दस्तक दे चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के लिए यह गर्व का दिन है क्योंकि भारत ने देश की आजादी के बाद स्वयं का संविधान बनाकर 26 जनवरी 1950 के दिन इसे लागू कर इसी दिन प्रभुत्ता सम्पन्न सार्वभौमिक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य बनने का गौरव हासिल किया था। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप मनाने की शुरूआत के पीछे मूल भावना यही थी कि देश का प्रत्येक नागरिक इस दिन संविधान की मर्यादा की रक्षा करने, स्वयं को देशसेवा में समर्पित करने तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति आस्था का संकल्प ले, साथ ही इन पर अमल करे लेकिन विडम्बना है कि गौरवान्वित कर देने वाले इस विशेष अवसर पर ऐसे संकल्पों को प्रतिवर्ष दोहरा कर या स्मरण मात्र करते हुए हम अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों की इतिश्री कर लेते हैं।

सही मायनों में गणतंत्र की मूल भावना को हमने आज तक समझा ही नहीं। 'गणतंत्र' का अर्थ है शासन तंत्र में जनता की भागीदारी। हालांकि हम कह सकते हैं कि शासन तंत्र में जनता को पूर्ण भागीदारी मिली है किन्तु क्या यह वाकई पूर्ण सत्य है? देश का संविधान लागू होने के इन 75 वर्षों में भी क्या वास्तव में शासन तंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है? जनता को यह तो अधिकार है कि मतदान के जरिये वह अपना जनप्रतिनिधि चुने किन्तु एक बार संसद अथवा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अगले पांच वर्षों तक इन जनप्रतिनिधियों पर उसका क्या कोई अंकुश रह जाता है? वास्तविकता यही है कि इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दल देश की जनता का चुनाव के समय महज एक वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं और अपना मतलब निकलने पर जनप्रतिनिधियों पर जनता के दुख-दर्द के बजाय अपने लिए सुख-सुविधाओं का अंबार जुटाने की चिंता सवार हो जाती है और वे इसी कवायद में जुट जाते हैं कि येन-केन-प्रकारेण अगले चुनाव के लिए कैसे करोड़ों रुपयों का इंतजाम किया जाए।

अहम सवाल यह है कि जिस राष्ट्र में जनता की भागीदारी चुनाव में सिर्फ वोट डालने और उसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण से शर्मसार होकर आंसू बहाने तक सीमित रह गई हो, वहां 'गणतंत्र' का भला क्या महत्व रह गया है? खासतौर से ऐसी स्थिति में, जब गरीबी व भुखमरी से त्रस्त करोड़ों लोग चंद रुपयों की खातिर या लाखों लोग महज दो-चार शराब की बोतलों के लिए अपने वोट बेच डालते हों या ईवीएम के दौर में भी कुछ मतदान केन्द्रों पर गुंडागर्दी के बल पर वोट डलवाये जाते हों?

हालांकि इसमें संशय नहीं कि हमें विशुद्ध रूप में एक प्रजातांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों के लिए बराबरी के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी की गई है, प्रत्येक नागरिक के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है किन्तु गणतांत्रिक भारत में पिछले 75 वर्षों के हालात का विवेचन करें तो यही पाते हैं कि हमारे कर्णधार एवं नौकरशाह किस प्रकार संविधान के कुछ प्रावधानों के लचीलेपन का अनावश्यक लाभ उठाकर कदम-कदम पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार करते रहे हैं। निःसंदेह इससे लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती रही है। संविधान निर्माताओं ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन लोगों के कंधों पर संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी, वही इसके प्रावधानों का मखौल उड़ाते नजर आएंगे। ऐसी दयनीय परिस्थितियों को देखकर निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं की आत्मा खून के आंसू रोती होगी।

संसद-विधानसभाओं में एक-दूसरे के साथ मारपीट, घूंसेबाजी, चप्पल, माइक इत्यादि से प्रहार, कुर्सियां फेंकने जैसी घटनाएं भारतीय लोकतंत्र में शर्मनाक पैठ बना चुकी हैं। वक्त-बेवक्त संसद और विधानसभाओं के भीतर होती गुंडागर्दी सरीखी घटनाएं दुनियाभर में हमें शर्मसार करती रही हैं। जिस राष्ट्र में कानून बनाने वाले और देश चलाने वाले लोग ही ऐसी असभ्य हरकतें करने लगें, वहां अपराधों पर अंकुश लगाने की किससे अपेक्षा की जाए? संसद-विधानसभा सरीखे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिरों में अपराधियों व बाहुबलियों का निर्बाध प्रवेश क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है? चुनाव जीतने के लिए आज हर राजनीतिक दल में ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने, चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल करने के अलावा उन्हें ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वा कर अपनी सीटें बढ़ाने के फेर में ऐसे दागी लोगों को लोकतंत्र के मंदिरों में प्रवेश दिलाने की होड़-सी लगी है। अदालतें जब भी संसद या विधानसभाओं में आपराधिक तत्वों का प्रवेश रोकने की दिशा में कुछ सार्थक पहल करने की कोशिश करती हैं, तमाम राजनीतिक दल उसे संसद के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक दखलंदाजी करार देते हुए हो-हल्ला मचाने लगते हैं।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सांसदों-विधायकों की रुचि लगातार कम हो रही है। प्रत्येक संसद सत्र में हंगामा व शोरशराबा करके संसद का बेशकीमती समय नष्ट कर देना जैसे एक परम्परा बन चुकी है। सदन से बहुत से सदस्य लंबे-लंबे समय तक गैरहाजिर रहते हैं। सर्वसम्मति के अभाव में देशहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण बिल लंबे समय तक लटके पड़े रहते हैं लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्ते अथवा अन्य ऐशोआराम की सुविधाएं बढ़ाने की बात आती है तो पूरा सदन एकजुट हो जाता है और ऐसे मामलों में पलक झपकते ही सर्वसम्मति बन जाती है। तब सदन में सदस्यों की उपस्थिति संख्या भी देखते ही बनती है। एक समय था, जब संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक बहस होती थी लेकिन अब हर संसद सत्र हंगामे और शोरशराबे की भेंट चढ़ जाता है।

इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि संसद का एक-एक मिनट बहुमूल्य होता है। संसद के प्रत्येक मिनट के कामकाज पर ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च होते हैं अर्थात् आठ घंटे की संसद की कार्रवाई पर बारह करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च होते हैं। आए दिन इसी तरह संसद में हंगामे होने, सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने या सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने से देश को कितना आर्थिक नुकसान होता है, इसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। संसद अथवा विधानसभाओं की कार्यवाही पर होने वाला यह भारी-भरकम खर्च जनप्रतिनिधियों की जेबों से नहीं निकलता बल्कि इसका सारा बोझ देश की आम जनता वहन करती है। बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 'गणतंत्र' की जो तस्वीर हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, क्या हम उस पर गर्व कर सकते हैं? गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का सही लाभ तभी है, जब न केवल देश का प्रत्येक नागरिक बल्कि बड़े-बड़े राजनेता और नौकरशाह भी संविधान की गरिमा को समझें और उसके अनुरूप अपने आचरण में पारदर्शिता भी लाएं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

हम सब भारत के लोग, भारत हम सबकी पहचान

हृदयनारायण दीक्षित

उत्सव और उल्लास आनंद देते हैं। भारत ने 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। संविधान 26 जनवरी के दिन पूरा प्रवर्तित हुआ। भारतीय संविधान सभा की आखिरी बैठक (26 नवम्बर 1949) में डॉ. आम्बेडकर के प्रस्ताव पर मतदान हुआ और संविधान पारित हो गया। भूमि, जन और शासन से ही राष्ट्र नहीं बनते। जाति, मजहब, राजनीति और क्षेत्रीय आग्रह समाज तोड़ते हैं, संस्कृति ही इन्हें जोड़ती है।

संविधान निर्माता सनातन सांस्कृतिक क्षमता से परिचित थे। उन्होंने संविधान की हस्तलिखित प्रति में सांस्कृतिक राष्ट्रभाव वाले 23 चित्र सम्मिलित किए। मुखपृष्ठ पर राम और कृष्ण तथा भाग 1 में सिन्धु सभ्यता की स्मृति वाले मोहनजोदड़ो काल की मोहरों के चित्र हैं। भाग 2 नागरिकता वाले अंश में वैदिक काल के गुरूकुल आश्रम का दिव्य चित्र है। भाग 3-मौलिक अधिकार वाले पृष्ठ पर श्रीराम की लंका विजय व भाग 4-राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले पन्ने पर कृष्ण अर्जुन उपदेश वाले चित्र हैं। भाग 5 में महात्मा बुद्ध, भाग 6 में स्वामी महाबीर और भाग 7 में सम्राट अशोक के चित्र हैं। भाग 8 में गुप्त काल, भाग 9 में विक्रमादित्य, भाग 10 में नालंदा विश्वविद्यालय, भाग 11 में उड़ीसा का स्थापत्य, भाग 12 में नटराज, भाग 13 में भगीरथ द्वारा गंगावतरण, भाग 14 में मुगलकालीन स्थापत्य, भाग 15 में शिवाजी और गुरू गोविन्द सिंह, भाग 16 में महारानी लक्ष्मीबाई, भाग 17 व 18 में क्रमशः गांधीजी की दाण्डी यात्रा व नोआखाली दंगों में शान्ति मार्च, भाग 19 में नेताजी सुभाष, भाग 20 में हिमालय, भाग 21 में रेगिस्तानी क्षेत्र व भाग 23 में लहराते हिन्दु महासागर की चित्रावलि है।

संविधान पारण के बाद अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने कहा अब सदस्यों को संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने हैं, एक हस्तलिखित अंग्रेजी की प्रति है, इस पर कलाकारों ने चित्र अंकित किये हैं, दूसरी छपी हुई अंग्रेजी व तीसरी हस्तलिखित हिन्दी की। (संविधान सभा कार्यवाही खण्ड 12 पृष्ठ 4261) भारतीय संस्कृति और इतिहास के छात्रों के लिए संविधान की चित्रमय प्रति प्रेरक हैं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा के आखिरी भाषण (26.11.1949) में कहा, संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या न करे, देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा, जो देश पर शासन करेंगे। उन्होंने दो बातों को लेकर खेद व्यक्त किया, केवल दो खेद की बाते हैं। मैं विधायिका के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करना पसंद करता। असंगत है कि विधि के शासन में सहायकों के लिए हम उच्च अर्हता का आग्रह करें लेकिन विधि निर्माताओं के लिए निर्वाचन के अलावा कोई अर्हता न रखें। विधि निर्माताओं के लिए बौद्धिक उपकरण अपेक्षित हैं। सामर्थ्य व चरित्र बल भी। दूसरा खेद यह है कि हम अपना संविधान भारतीय भाषा में नहीं बना सके।

संविधान सभा के आखिरी भाषण में डॉ. अम्बेडकर ने भी प्राचीन भारतीय परम्परा की याद दिलाते हुए कहा था एक समय था जब भारत गण राज्यों से सुसज्जित था। यह बात नहीं है कि भारत पहले संसदीय प्रक्रिया से अपरिचित था। भारत संसदीय प्रक्रिया से पहले भी सुपरिचित था। यहां वैदिक काल से ही एक परिपूर्ण गणव्यवस्था थी। गणेश गणपति थे। प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख ऋग्वेद में गणांना त्वां गणपतिं आया है। मार्क्सवादी चिंतक डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है गण पुराना शब्द है, यह पुरानी समाज व्यवस्था का द्योतक है। गण और जन ऋग्वेद में पारिभाषिक हो गये हैं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म से आदर्श गणतंत्र के सूत्र पूछे। भीष्म ने (शांतिपर्व: 107.14) बताया कि भेदभाव से ही गण नष्ट होते हैं। उन्हें संघबद्ध रहना चाहिए।

राष्ट्रीय खेल के लिये यूपी का दल उत्तराखंड रवाना

एजेंसी

लखनऊ। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तर प्रदेश की टीमों की रवानगी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत भव्य विदाई के साथ हुई। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने ओलंपिक ध्वज दिखाकर उत्तर प्रदेश के दल को रवाना किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पाण्डेय ने किया। मुख्य अतिथि अवनीश कुमार अवस्थी ने मौजूद खिलाड़ियों को किट प्रदान कर उत्तर प्रदेश दल को किट वितरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों को अभूतपूर्व सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पाण्डेय ने बताया कि बेहतरीन तैयारियों के चलते उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इस बार अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष विराज सागर दास ने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने प्रेषित शुभकामना संदेश में कहा कि आप सभी मेहनत और लगन के साथ खेलते हुए प्रदेश का नाम रोशन करें।

नयना और हर्षित ने आइस-स्केटिंग में जीते स्वर्ण पदक

लेह (लद्दाख)। शीतकालीन खेलों के पांचवें संस्करण के दूसरे दिन तेलंगाना और कर्नाटक ने स्पीड स्केटिंग स्पर्धा में एक-एक स्वर्ण पदक जीते। आज यहां खेले गये स्केटिंग मुकाबलों में तेलंगाना की नयना श्री तल्लूरी ने केआईडब्ल्यूजी 2025 का पहला स्वर्ण पदक जीता और एनडीएस स्टेडियम में महिलाओं की 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर 'हैट्रिक' पूरी की। कर्नाटक के हर्षित ने गुपुक्स पॉन्ड में दिन का दूसरा स्केटिंग स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक के ही हर्षन दूसरे तथा हरियाणा के सचिन सिंह तीसरे स्थान पर रहे। स्पीड स्केटिंग 500 मीटर महिला फाइनल में तेलंगाना की नयना श्री तल्लूरी 1:01.35 समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, कर्नाटक की प्रतीक्षा केएस 1:02.84 समय के साथ दूसरे तथा महाराष्ट्र की स्वरूपा देशमुख 1:03.15 समय के साथ तीसरे स्थान पर रही स्पीड स्केटिंग 1000 मीटर लंबे ट्रैक पुरुष फाइनल में कर्नाटक के हर्षित बीटी ने 1:44.22 समय के साथ स्वर्ण तथा तमिलनाडु के गुरु हर्षन एच 1:55.38 के साथ दूसरे तथा हरियाणा के सचिन सिंह 1:56.63 समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

त्रिवेदी ने काता स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक

अहमदाबाद। पश्चिम रेलवे के दिवेश त्रिवेदी ने काता स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के मुख्य कार्यालय अधीक्षक/परिचालन विभाग श्री त्रिवेदी ने 55 से 60 वर्ष आयु वर्ग में एक्सआईआई जेकेएआई (जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया) सीनियर कराटे चैंपियनशिप के काटा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। श्री त्रिवेदी 1985 से कराटे का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने 1991 में जापान कराटे एसोसिएशन की पहली डैन ब्लैक बेल्ट परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसका मुख्यालय टोक्यो, जापान में है। वर्तमान में वे जापान कराटे एसोसिएशन के छठे डैन ब्लैक बेल्ट हैं। जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जेकेएआई इंडिया) ने 18 से 22 जनवरी तक हैदराबाद के गाचीबोली इंडोर स्टेडियम में जेकेए इंडिया के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। चैंपियनशिप में दुनिया भर से 1600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 64 छात्र महाराष्ट्र से थे।

राष्ट्रीय खेलों में आईओसीएल आया साथ, ब्रॉन्ज स्पॉन्सर बना

नैनीताल/देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे उत्तराखंड को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) का साथ मिल गया है। आईओसीएल प्रायोजक के रूप में उत्तराखंड का साथ देगा। आईओसीएल की ओर से आधिकारिक सहमति दे दी गई है। आईओसीएल को राष्ट्रीय खेलों का ब्रांज स्पॉन्सर बना दिया गया है। अब इस आयोजन के प्रचार-प्रसार में अब आईओसीएल भी भागीदार होगा। आईओसीएल की ओर से बतौर प्रायोजक जल्द ही अपनी भागीदारी को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्री खेलों के उद्घाटन के दिन आईओसीएल की बोर्ड बैठक भी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रायोजक के आकार पर निर्णय ले लिया जाएगा। बहरहाल, आईओसी ने स्पॉन्सरशिप के लिए प्रारंभिक सहमति दे दी है। राष्ट्रीय खेलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा के अनुसार आईओसीएल का स्पॉन्सरशिप के संबंध में आधिकारिक मेल प्राप्त हुआ है।

मंदिरी अंडर-20 चैलेंज सीरीज के लिए एआईएफएफ टीम में सुदेवा दिल्ली एफसी के तीन खिलाड़ी चयनित

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रतिष्ठित मंदिरी अंडर-20 चैलेंज सीरीज के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की 23 सदस्यीय टीम में सुदेवा दिल्ली एफसी के तीन मौजूदा खिलाड़ियों का चयन हुआ है। क्लब ने उक्त घोषणा की। सुदेवा दिल्ली एफसी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, यह पूरे सुदेवा परिवार के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि चयनित खिलाड़ी - फॉरवर्ड मोहम्मद जुल्किफ, मिडफील्डर मोहम्मद समी और जाजो प्रशान - भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं को विकसित करने और मिशन विश्व कप 2030 के प्रति सुदेवा के समर्पण का प्रमाण हैं। इन मौजूदा खिलाड़ियों के अलावा, सुदेवा के दो पूर्व छात्र, जो प्रमुख क्लबों के लिए खेलने के लिए आगे बढ़े हैं, ने भी टीम में अपनी जगह बनाई है। गोलकीपर करण मक्कर वर्तमान में जमशेदपुर एफसी के साथ और डैनी मीतेई लैशराम, मिडफील्डर वर्तमान में नॉर्थ-ईस्ट यूनाइटेड के साथ हैं, जो अकादमी

के व्यापक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के स्थायी प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, 2014 में स्थापित सुदेवा भारत का अग्रणी आवासीय प्रशिक्षण संस्थान है, जो देश भर से फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज और पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरदराज के क्षेत्रों से खिलाड़ियों की खोज और विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के साथ, सुदेवा का जमीनी स्तर का युवा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए आशा की किरण बन गया है। एआईएफएफ द्वारा एक एलीट अकादमी के रूप में मान्यता प्राप्त और खेलो इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त अकादमी, खिलाड़ियों के विकास के लिए समर्पित है, जिसमें शिक्षा और जीवन कौशल के साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण का संयोजन किया जाता है। हाल ही में हुए चयन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार शीर्ष स्तरीय एथलीटों को तैयार करने के सुदेवा के मिशन की सफलता को उजागर करते हैं। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ अकादमी के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कौशल विकास पर रणनीतिक ध्यान और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। मंदिरी अंडर-20 चैलेंज सीरीज़ एक बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट है जो पूरे क्षेत्र से शीर्ष युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को एक साथ लाता है। एआईएफएफ की 23 सदस्यीय टीम देश की सबसे उज्ज्वल संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, और इस टीम में सुदेवा का योगदान वैश्विक मंच पर भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने में इसकी प्रमुख भूमिका को रेखांकित करता है।

सूरमा हॉकी क्लब ने श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स को 4-2 से हराया

रांची। सूरमा हॉकी क्लब ने गुरुवार को महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग आखिरी पूल चरण में श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स को 4-2 से हरा टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सूरमा हॉकी क्लब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में ओडिशा वारियर्स से भिड़ेगा। आज रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब के लिए चार्लोट एंगलबर्ट ने (पहले, 17वें और 47वें) मिनट में गोलकर शानदार हैट्रिक बनाते हुए खेल पर अपना दबदबा बनाये रखा। हिना बानो ने (नौवें) मिनट में सूरमा के लिए गोल दागा।

श्रीची राढ़ बंगाल टाइगर्स के लिए कप्तान वंदना कटारिया ने (48वें) मिनट और शिल्पी डबास ने आखिरी क्वार्टर के (58वें) मिनट में गोल किया।

टी-20 जय नेपाल कप: काठमांडू विश्वविद्यालय को हराकर लखनऊ विश्वविद्यालय सेमीफाइनल में

एजेंसी

लखनऊ । त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमांडू, नेपाल में खेले जा रहे टी-20 जय नेपाल कप क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने दूसरे मैच में काठमांडू विश्वविद्यालय को 87 रन से हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। लखनऊ विश्वविद्यालय के कप्तान आनंद सागर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 20 ओवर में चार विकेट पर 160 रन बनाये। टीम से मन कांडपाल ने सबसे ज्यादा नाबाद 75 रन बनाए। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 28, आदित्य प्रताप ने 25 और आशीष यादव ने 17 रन का योगदान दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी काठमांडू विश्वविद्यालय को अभिषेक ने पहला झटका दिया। इसके बाद टीम में वापसी नहीं कर सकी और 20 ओवर में 8 विकेट पर 87 रन ही बना सकी। लखनऊ विश्वविद्यालय से आनंद सागर ने 3 विकेट लिए।

मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मनन कांडपाल को नाबाद 75 रन और 1 विकेट लेने के लिए मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय का आखिरी लीग मैच कल दोपहर 1 बजे से मिड वेस्ट यूनिवर्सिटी के खिलाफ होगा।मैच के बाद उपकप्तान व मैन ऑफ द मैच मनन कांडपाल ने जीत का श्रेय कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय को समर्पित किया। क्रीडा परिषद के महासचिव प्रो. अजय कुमार आर्य समस्त टीम के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को बधाई और अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी ।

राष्ट्रीय खेल में शामिल होने को खिलाड़ी हुए रवाना,अवनीश अवस्थी ने दिखायी हरी झंडी

एजेंसी

लखनऊ। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तर प्रदेश की टीमों की रवानगी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत भव्य विदाई के साथ हुई। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि अवनीश कुमार अवस्थी (सलाहकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश) ने ओलंपिक ध्वज दिखाकर उत्तर प्रदेश के दल को रवाना किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पाण्डेय ने किया।मुख्य अतिथि अवनीश कुमार अवस्थी ने मौजूद खिलाड़ियों को किट प्रदान कर उत्तर प्रदेश दल को किट वितरण की शुरुआत की। उन्होंने अपने आर्शीवचन में कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेलों को अभूतपूर्व सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पाण्डेय ने बताया कि बेहतरीन तैयारियों के चलते उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इस बार अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विराज सागर दास ने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने प्रेषित शुभकामना संदेश में कहा कि आप सभी मेहनत और लगन के साथ खेलते हुए प्रदेश का नाम रोशन करें। हम सभी को आप पर गर्व है और हमें विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा से नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए अब तक उत्तर प्रदेश की कलारीपयट्टु, ट्रायथलॉन, हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल, योगासन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, तीरंदाजी व बाक्सिंग टीम को किट प्रदान की चुकी है।

मुंबई सिटी एफसी ने स्पेनिश अटैकर जॉर्ज ऑर्टिज से किया करार

एजेंसी

मुंबई। मुंबई सिटी एफसी ने स्पेनिश अटैकर जॉर्ज ऑर्टिज के साथ करार किया है। स्पेन के विलाकैनास से आने वाले ऑर्टिज़ 2025-2026 सीज़न के लिए मुंबई सिटी एफसी में शामिल होंगे और अपने अनुभव और गुणवत्ता को टीम में लाने की कोशिश करेंगे। गेटाफे सीएफ की युवा प्रणाली के उत्पाद, ऑर्टिज़ ने स्पेन में एक प्रभावशाली करियर बनाया है, जिसमें एटलेटिको मैड्रिड बी के साथ एक स्पेल भी शामिल है। 2022 में, वह शेन्ज़ेन पेंग सिटी में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने 2022-2023 तक चाइना लीग वन में खेला और 2024 में चीनी सुपर लीग में भाग लिया, जिसमें 56 मैचों में कुल 15 गोल और 11 सहायता दर्ज की गई। ऑर्टिज एएफसी स्तर पर भी अनुभव लाते हैं, 2021 एएफसी चैंपियंस लीग में प्रमुखता से शामिल हुए और स्कोरिंग की। आईएसएल में ऑर्टिज ने 14 गोल और 8 सहायता के साथ

36 मैच खेले हैं। वर्तमान इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) सीज़न के महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके हस्ताक्षर से आइलैंडर्स की टीम मजबूत होगी। जॉर्ज ऑर्टिज ने मुंबई सिटी एफसी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के हवाले से कहा, मैं इंडियन सुपर लीग में वापस आकर, मुंबई सिटी एफसी जैसे रोमांचक क्लब में शामिल होने और सिटी फुटबॉल ग्रुप के भीतर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ। क्लब और ग्रुप दोनों ने बहुत उच्च मानक स्थापित किए हैं। मुंबई शहर और मुंबई सिटी एफसी का माहौल बेजोड़ है, और मैं अपने नए साथियों, प्रशंसकों के साथ शुरुआत करने और उनकी सफलता में योगदान देने के लिए उत्सुक हूँ,

मुंबई सिटी एफसी के मुख्य कोच पेट्र क्रेटकी ने कहा, हम मुंबई सिटी एफसी में ऑर्टिज का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं। वह आईएसएल में सिद्ध क्षमता वाले एक हमलावर हैं और उन्हें उच्च स्तर पर खेलने का अनुभव है। हम हमेशा बेहतर होने का प्रयास करते हैं और मैदान पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। इस लिहाज से, ऑर्टिज इस सीज़न में हमारी टीम को मजबूत करेंगे। हम उनके शामिल होने से उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि हम शेष सीज़न में भी सफलता हासिल करेंगे।

उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के तकनीकी अधिकारी व पर्यवेक्षक बने डॉ. अजय पाठक

एजेंसी

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव व मंडलीय ओलंपिक सचिव मुरादाबाद निवासी डॉ. अजय पाठक उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के तकनीकी अधिकारी व पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। क्षेत्रीय कीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसमें डॉ. अजय पाठक को तकनीकी अधिकारी व पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। डॉ. अजय मुरादाबाद मंडल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने लगातार दूसरी बार तकनीकी अधिकारी/पर्यवेक्षक बनाया है।

इस उपलब्धि के मिलने के बाद डॉ. अजय पाठक ने बताया कि हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि उत्तर

प्रदेश के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उत्तर प्रदेश की टीम ज्यादा ज्यादा मैडल जीते और अंक तालिका में में टॉप पर रहे।

हसन अली 2025 तक वारविकशायर में वापसी के लिए सहमत

एजेंसी

नई दिल्ली। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने 2025 में क्लब के लिए सभी प्रारूपों में खेलने के लिए वारविकशायर में वापसी पर सहमति व्यक्त की है। उनके मई में टी20 ब्लास्ट की शुरुआत से लेकर सितंबर के अंत तक उपलब्ध रहने की उम्मीद है। 30 वर्षीय हसन पिछले सीजन में एजबेस्टन में अपने कार्यकाल के दौरान कोहनी की चोट के बाद से नहीं खेले हैं, जिसके कारण उन्हें पांच विटैलिटी ब्लास्ट मैचों में 10 विकेट लेने के बाद बाहर होना पड़ा। सर्जरी के बाद वे वारविकशायर और पाकिस्तान के मेडिकल स्टाफ दोनों की देखरेख में पुनर्वास से गुजर रहे हैं। उन्होंने क्लब की आधिकारिक वेबसाइट के हवाले से कहा, मैंने पिछले साल कहा था कि एजबेस्टन मुझे दूसरे घर जैसा लगता है...लेकिन अब यह पहले घर जैसा होता जा रहा है। मुझे वारविकशायर के लिए खेलना, बियर्स के प्रशंसकों के लिए खेलना पसंद है। और मुझे उम्मीद

है कि वे मेरे खेलने के तरीके से देखेंगे कि मैं इस क्लब के लिए कितना जीतना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, 2023 में व्हाइट बियर कैप से सम्मानित होना मेरे करियर के सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक था और मैं अगले सीज़न में बियर्स के साथ और भी कई खास यादें बनाना चाहता हूँ। पिछला साल चोट के कारण बदकिस्मत रहा। मुझे लगा कि मैं अच्छी गेंदबाजी कर रहा था और ब्लास्ट में काफी विकेट ले रहा था। लेकिन मैं ट्रेनिंग में 100 प्रतिशत गेंदबाजी कर रहा हूँ और अगले सीज़न में वारविकशायर के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। हसन ने 2023 और 2024 सीज़न में वारविकशायर के लिए नौ काउंटी चैंपियनशिप में 27 विकेट लिए हैं, साथ ही ब्लास्ट में 19 विकेट लिए हैं।

मंगलुरु में 200 से अधिक तैराक डेन डेन सी स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए तैयार

एजेंसी

मंगलुरु। डेन डेन सी स्विमिंग चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण को शानदार प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 200 से अधिक तैराक 26 जनवरी को मंगलुरु सर्फ क्लब बीच पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस इवेंट का आयोजन मंगलुरु सर्फ क्लब द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 250 मीटर से लेकर 6 किमी तक की पांच श्रेणियों में मुकाबले होंगे। इस बार का मुख्य आकर्षण डूबे हुए डेन डेन जहाज के चारों ओर आयोजित दौड़ है, जो 2007 में समुद्र में डूबने के बाद एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। प्रतियोगिता में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा समेत कई राज्यों के तैराक भाग लेंगे। प्रतिभागी 10 वर्ष से ऊपर के आयु-विशिष्ट वर्गों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सबसे लंबी श्रेणी 6 किमी की दौड़ होगी। मंगलुरु सर्फ क्लब के अध्यक्ष चिराग शंभू ने इस आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा, इस साल की चैंपियनशिप में प्रतिभागियों की संख्या पिछले साल से दोगुनी हो गई है। यह भारत में ओपन-वाटर स्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। हम जल सुरक्षा को बढ़ावा देने और मंगलुरु को इस तरह के आयोजनों के लिए प्रमुख स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चैंपियनशिप के निदेशक ऋषभ शेट्टी ने बताया कि सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 20 से अधिक लाइफगार्ड, स्पीडबोट्स और सर्फ-बोट्स की सहायता से सभी प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया है, उन्होंने कहा। इस इवेंट को भारतीय तट रक्षक, हॉलीवुड लाउंज, केएमसी अस्पताल और वी वन एक्वाटिक सेंटर जैसे साझेदारों का सहयोग मिला है। इसके अलावा, ओपन वाटर स्विमर्स फाउंडेशन और लोकल फिशिंग बोट्स ने भी सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दिया है।

बार्सिलोना के डिफेंडर जेरार्ड मार्टिन ने नए अनुबंध पर किए हस्ताक्षर

एजेंसी

मैड्रिड। एफसी बार्सिलोना के स्टार डिफेंडर जेरार्ड मार्टिन ने 30 जून 2028 तक क्लब के साथ अनुबंध विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने 23वें जन्मदिन से दो दिन पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लब ने उक्त घोषणा की। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने पहली टीम में अपने सफल सत्र में प्रभावित किया है, बी-टीम से पदोन्नति के बाद 18 बार प्रदर्शन किया है। क्लब के बयान में कहा गया है, एफसी बार्सिलोना और जेरार्ड मार्टिन ने क्लब के साथ खिलाड़ी के अनुबंध को 30 जून 2028 तक बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। डिफेंडर ने गुरुवार को दोपहर में बार्सा के अध्यक्ष जोआन लापोर्टा, युवा फुटबॉल के लिए जिम्मेदार निदेशक जोआन सोलर, खेल निदेशक एंडरसन लुइस डी सूजा (डेको) और युवा फुटबॉल के निदेशक जोस रेमन एलेक्सेंको की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। डिफेंडर ने बार्सिलोना की वेबसाइट से कहा, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं बचपन से ही बार्सिलोना का समर्थक रहा हूं और जब मैं यहां आया, तो मुझे पहली टीम में शामिल होने की उम्मीद थी। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने इसे प्रबंधित किया है और मैं खुश हूं। मार्टिन ने

कहा, मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा और जो भी अवसर मुझे मिलेंगे, उनका लाभ उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य जितना संभव हो सके, क्लब के लिए उतने अधिक खिताब जीतना है।

खो-खो विश्व कप विजेता भारतीय टीमों को केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने दी बधाई, महाराष्ट्र सरकार ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा तोहफा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने हाल ही में खो-खो विश्व कप जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। खडसे ने कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है कि दोनों टीमों ने इस स्वदेशी खेल में पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने इस जीत को पूरे देश, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणा बताया।खडसे ने कहा, 'हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जिस दबदबे के साथ विश्व कप जीता, उससे मुझे बहुत गर्व है। यह हमारी मिट्टी और गांवों का खेल है, जिसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआई) और खिलाड़ियों को जाता है।'उन्होंने केकेएफआई के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इस खेल को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है।भारतीय पुरुष टीम, जिसकी कप्तानी प्रतीक वाइकर कर रहे थे, ने फाइनल मुकाबले में नेपाल को हराया। वहीं, महिला टीम ने प्रियंका इंगले की अगुवाई में नेपाल के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहले खो-खो विश्व कप में 6 महाद्वीपों के 23 देशों की 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट एक सप्ताह तक चला, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा।

महाराष्ट्र ने निभाई अग्रणी भूमिका

खडसे ने महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और कहा, 'महाराष्ट्र, जहां इस खेल की शुरुआत हुई, ने शानदार योगदान दिया। अब यह हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में इस खेल को बढ़ावा दें और नई पीढ़ी को प्रेरित करें।'

राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने 10 दिसंबर, 2024 से 11 जनवरी, 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक महीने का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 27 राज्यों के 60 पुरुष और 60 महिलाओं ने भाग लिया, जिसे केकेएफआई के समर्थन से आयोजित किया गया।

मित्तल ने सरकार की सराहना की

केकेएफआई के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने विश्व कप के सफल आयोजन में सहयोग के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, 'खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने हर संभव सहायता प्रदान की। हमने चार साल बाद बर्मिंघम में अगले विश्व कप के आयोजन की घोषणा कर दी है और भारत में भविष्य की विश्व चैम्पियनशिप आयोजित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं।' खडसे के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार ने खो-खो विश्व कप में भाग लेने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 2.25 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार और राज्य सरकार में प्रथम श्रेणी की नौकरी देने की घोषणा की है। यह कदम खो-खो को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयासों का हिस्सा है।

खो-खो को नई पहचान देने का प्रयास

रक्षा खडसे ने कहा कि सरकार खो-खो जैसे स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि केकेएफआई की योजनाओं को आगे बढ़ाने और खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री से चर्चा की जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने शुरू की बजट 2025 की तैयारी, बजट सेरेमनी में लिया हिस्सा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज हलवा समारोह में हिस्सा लिया, जो आम तौर पर 24 जनवरी को आयोजित किया जाता है। यह केंद्रीय बजट तैयार करने का अंतिम चरण है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। हलवा समारोह 'लॉक-इन' अवधि की शुरुआत का प्रतीक है, जिसके दौरान बजट तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी संसद में इसे पेश किए जाने तक मंत्रालय परिसर में ही रहते हैं। इस दौरान उनके फोन कॉल की भी निगरानी की जाती है। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है और सीसीटीवी कैमरों और खुफिया ब्यूरो द्वारा उन पर लगातार नज़र रखी जाती है। मीठे व्यंजनों का भारत में एक मजबूत सांस्कृतिक महत्व है और इन्हें किसी भी अवसर के लिए शुभ माना जाता है। हर साल बजट से पहले, पारंपरिक मीठा व्यंजन हलवा दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक बड़ी कड़ाही में तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री इसे विधिवत रूप से इसमें अपनी परम्परागत भूमिका निभाते हैं। हलवा तैयार होने के बाद इसे बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है।

अमूल ने दूध की कीमत एक रुपये प्रति लीटर घटाई, नई दरें लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। अमूल कंपनी ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दूध की कीमतों में एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके साथ ही देशभर में अमूल का दूध एक रुपये सस्ता हो गया है। नई दरें शुक्रवार से प्रभावी हो गई है। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ के प्रबंध निदेशक (एमडी) जयेन मेहता ने एक बयान में कहा कि अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और अमूल टी स्पेशल एक लीटर पैक दूध की कीमत 1 रुपये घटा दी गई है। इस कटौती के बाद अब अमूल गोल्ड का एक लीटर पैक 66 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि आधे लीटर का पैक 33 रुपये का होगा। अमूल ताजा दूध अब 54 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि आधे लीटर का पैक 27 रुपये में मिलेगा। अमूल शक्ति का एक लीटर पैक अब 60 रुपये में उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि लंबे समय के बाद दूध की कीमत में कटौती की गई है। पिछले कुछ समय में सभी कंपनियों ने दूध के दाम में इजाफा किया था, लेकिन अमूल के दूध के भाव में कटौती करने से अन्य कंपनियों पर भी दूध के रेट घटाने का दबाव बढ़ेगा।

अच्युत घटक कोल इंडिया बोर्ड में निदेशक 'तकनीकी' नियुक्त, कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अच्युत घटक को बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) नियुक?त किया है। अच्युत घटक ने अपना कार्यभार आज संभाल लिया। उन?होंने बी. वीरा रेड्डी का स्थान लिया, जो पिछले वर्ष अगस्त में सेवानिवृत्त हो गए थे। कोल इंडिया ने जारी बयान में कहा कि अच्युत घटक को बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि 23 जनवरी, 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी। सीआईएल ने अच्युत घटक के निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभालने की जानकारी दी है। कोल इंडिया ने कहा कि हमें अच्युत घटक को डी(टी) सीआईएल के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उन?होंने 1989 में हमारी सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स में जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले अच्युत घटक कोयला खनन क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री से मुलाकात में आंध्र प्रदेश के लिए मांगी वित्तीय सहायता

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नई दिल्ली में मुलाकात की।मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू ने राज्य से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर चर्चा करके वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नार्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू ने राज्य से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर चर्चा की और वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। चर्चा के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों में अमरावती के लिए हुडको ऋण और विश्व बैंक से वित्त पोषण शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी चर्चा करेंगे। नई दिल्ली में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद एन. चंद्रबाबू नायडू के आज शाम विजयवाड़ा लौटने की उम्मीद है।

सर्राफा बाजार में सपाट स्तर पर कारोबार, सोना और चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार आज सपाट स्तर पर कारोबार कर रहा है। सोना और चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में बदलाव नहीं होने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज भी 82,090 रुपये से लेकर 82,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज गुरुवार के भाव पर ही यानी 75,250 रुपये से लेकर 75,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं होने के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में ये चमकीली धातु आज लगातार तीसरे दिन 96,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर

कारोबार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 82,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 75,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 82,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 75,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 82,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 75,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज भी 82,090 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 75,250 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 82,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 75,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 82,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 75,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ईएसआई के तहत नवंबर, 2024 में 16.07 लाख नए श्रमिक नामांकित

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने नवंबर माह में 16.07 लाख नए कर्मचारियों को ईएसआई योजना के तहत जोड़ा है। इससे पिछले महीने ईएसआईसी ने 17.80 लाख नए सदस्यों को जोड़े थे। इसके साथ ही नवंबर, 2024 तक 20,212 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में बताया कि ईएसआईसी ने नवंबर, 2024 के महीने में 16.07 लाख नए कर्मचारी जोड़े हैं। सालाना आधार पर नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर महीने में शुद्ध पंजीकरण में 0.97 फीसदी की वृद्धि हुई है। अनंतिम पेरोल आंकड़ों के मुताबिक नवंबर, 2024 में 20,212 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। इससे और ज्यादा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने के दौरान जोड़े गए कुल 16.07 लाख कर्मचारियों में से 7.57 लाख कर्मचारी कुल पंजीकरण का लगभग 47.11 फीसदी है, जो 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। इस दौरान ईएसआई योजना में 3.28 लाख महिला सदस्यों का नामांकन रहा है। इसके अलावा नवंबर, 2024 में ईएसआई योजना के तहत 44 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ। यह समाज के हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है।

केंद्र ने जीएसटी उल्लंघन के लिए फर्जी समन जारी करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ लोगों को किया आगाह

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नागरिकों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) उल्लंघन के लिए फर्जी और धोखाधड़ी वाले समन जारी करने वाले धोखेबाजों को लेकर आगाह किया है।

वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी उल्लंघन के लिए फर्जी और धोखाधड़ी वाले समन जारी करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी है। सीबीआईसी ने कहा कि हाल ही में यह देखा गया है कि धोखाधड़ी के इरादे से कुछ व्यक्ति करदाताओं को फर्जी समन बना रहे हैं और भेज रहे हैं, जो जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की जांच के दायरे में हो भी सकते हैं और नहीं भी।मंत्रालय ने कहा कि सीबीआईसी के मुताबिक विभाग के विशेष प्रतीक चिन्ह (लोगो) और दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) के इस्तेमाल के कारण यह नकली समन मूल समन से बहुत मिलता-जुलता है। हालांकि, ये डीआईएन नंबर नकली हैं। ये धोखेबाजों द्वारा दस्तावेज को असली दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल

किया जाता है। यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि करदाता सीबीआईसी की वेबसाइट https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch ÂÚU ÒVERIFY CBIC-DINÓ विंडो का उपयोग करके सीबीआईसी के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किसी भी संचार (समन सहित) की वास्तविकता को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।डीआईएन की पुष्टि करने पर यदि कोई व्यक्ति या करदाता पाता है कि समन/पत्र/नोटिस फर्जी है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित कार्यालय को दी जा सकती है। इससे सक्षम डीजीजीआई/सीजीएसटी गठन को जनता को ठगने के लिए फर्जी समन/पत्र/नोटिस का उपयोग करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ कानून प्रवर्तन कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

एमएनआरई इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में 'नए भारत का सूर्योदय' झांकी करेगा प्रदर्शित

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में आकर्षक झांकी प्रदर्शित करेगा, जिसमें वह भारत के उभरते ऊर्जा परिदृश्य की झलक दिखलाएगा। साथ ही देश की गहरी सांस्कृतिक विरासत मनाते हुए वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति दर्शाएगा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि यह झांकी मुख्य रूप से महत्वाकांक्षी पहल प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना पर केंद्रित होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आवासीय छत सौर पहल है। साथ ही इसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अन्य परिवर्तनकारी योजनाएं भी दर्शायी जाएंगी। एमएनआरई के ये प्रयास भारत की हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ ही वर्ष 2030 तक करोंड़ो हरित नौकरियों के अवसर उत्पन्न करेंगे।

मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के ऊर्जा परिवर्तन (संक्रमण) पर जोर देते हुए झांकी में हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी दर्शाया जाएगा। इसमें पवन ऊर्जा में चौथे

सबसे बड़े संस्थापन क्षमता वाले देश के रूप में भारत की स्थिति भी दर्शाई जाएंगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि संवहनीय और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर भारत के बढ़ते कदम की इस झांकी को देखने वाले पहले लोगों में पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम लाभार्थी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आमंत्रित नवीकरणीय ऊर्जा तकनीशियनों सहित आठ सौ विशेष अतिथि गणतंत्र दिवस परेड देखने वालों में शामिल होंगे। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी के नेतृत्व में यह मंत्रालय अपनी परिवर्तनकारी योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा भारत में लाखों परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.88 अरब डॉलर घटकर 623.98 अरब डॉलर पर

एजेंसी

मुंबई/नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7वें हफ्ते गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जनवरी को समाप्त हफ्ते में 1.88 अरब डॉलर घटकर 623.98 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले हफ्ते यह 8.71 अरब डॉलर घटकर 625.87 अरब यूएस डॉलर रहा था।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जारी आंकड़ों में बताया कि 17 जनवरी को समाप?त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.88 अरब डॉलर घटकर 533.13 अरब डॉलर रह गईं है। आंकड़ों के मुताबिक स्वर्ण भंडार का आरक्षित मूल्य 10.63 लाख डॉलर बढ़कर 68.95 अरब डॉलर हो गया है। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 10 लाख डॉलर घटकर 17.78 अरब डॉलर रहा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 7.4 करोड़ डॉलर घटकर 4.12 अरब डॉलर रह गया है।इससे पहले

सितंबर, 2024 के अंत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 704.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही गिरावट का कारण रुपये में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए आरबीआई का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के साथ-साथ मूल्यांकन माना जा रहा है।

डीपीआईआईटी ने विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए निजी फर्म से मिलाया हाथ

एजेंसी

नई दिल्ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने परिधानों के सबसे बड़े निर्माता शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी भाने ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि डीपीआईआईटी और भाने ग्रुप के साथ जो समझौता हुआ है। यह सहकार्यता विनिर्माण के साथ-साथ अन्य उत्पादन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू करेगा, जो अंतरराष?ट्रीय स्टार्टअप प्रणाली के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा। यह समझौता देश में नए विनिर्माण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि अपने व्यापक अनुभव से भाने समूह बाजार को लेकर आवश?यक जानकारी प्रदान

करके आगामी स्टार्टअप की मदद करेगी। भाने समूह स्टार्टअप्स को विदेशी बाजारों के कामकाज की समग्र समझ बनाने में मदद करेगी। इसके साथ ही स्टार्टअप जीवनचक्र के दौरान परिचालन ज्ञान पर मार्गदर्शन भी देगी। डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि इस सहयोग से बड़े लाभ की पूर्ति होगी, जिसमें एक समृद्ध उद्यमशीलता की भावना को पोषित करना और भारत के विनिर्माण परिदृश्य को मजबूत करना शामिल है। उन?होंने कहा कि स्टार्टअप और भाने समूह जैसे स्थापित खिलाड़ियों के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाकर हम एक पारस्परिक रूप से लाभकारी वातावरण को बढ़ावा देते हैं, जहां नवाचार पनपता है। इससे भारतीय व्यवसाय वैश्विक सफलता प्राप्त करते हैं। भाने ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक आनंद आहूजा ने कहा कि वैश्विक ब्रांड भारतीय स्टार्टअप में निवेश करने को तत?पर हैं, क्योंकि यह दक्षिण एशियाई बाज़ार में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है। स्टार्टअप इंडिया के साथ डीपीआईआईटी का मिशन भारतीय स्टार्टअप के बीच नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।

प्रीमियम लिस्टिंग के बावजूद लोअर सर्किट पर पहुंचे ईएमए पार्टनर्स के शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनी ईएमए पार्टनर्स के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में 26.21 प्रतिशत प्रीमियम के साथ एंट्री हुई। कंपनी के शेयर 124 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 156.50 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद खरीदारी के सपोर्ट से ये उछल कर 158.80 रुपये के स्तर तक पहुंचा। हालांकि थोड़ी ही देर बाद बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से ये गोता लगा कर 148.70 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर आ गया। लोअर सर्किट लगने के बावजूद प्रीमियम ओपनिंग के कारण कंपनी के आईपीओ निवेशक अभी भी 19.92 प्रतिशत के फायदे में हैं। ईएमए पार्टनर्स लिमिटेड का 76.01 करोड़ रुपये का

आईपीओ 17 से 21 जनवरी के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 221.06 गुना सब्सक्राइब हो गया था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 147.69 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 444.08 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 167.35 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 66.14 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 7.96 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बेचे गए हैं?। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी सब्सिडियरी में लीडरशिप टीम को बढ़ाने, अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, पुराने कर्ज को चुकाने और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी को 11.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2022-23 में घट कर 3.07 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इसके बाद 2023-24 में शुद्ध लाभ में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई और लाभ का ये आंकड़ा 38.41 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच कंपनी को 4.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका है। इसी तरह इस अवधि में कंपनी 26.33 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल कर चुकी है।

कोयला सचिव ने सीआईएल की सीएसआर पहल के तहत स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया

एजेंसी

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं (स्मार्ट क्लास रूम) का उद्घाटन किया, जिन्हें कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों की सीएसआर पहल 'डिजी विद्या' के तहत बनाया गया है। कोयला मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि सीएसआर पहल के तहत 'डिजी विद्या' का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आठ राज्यों के खनन क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जहां सीआईएल की सहायक कंपनियां काम करती हैं, ताकि उनमें से कोई भी 'विकसित भारत' की यात्रा में पीछे न छूट जाए। पहले चरण में डिजी विद्या के तहत 272 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं के साथ अपग्रेड किया गया। आगामी चरणों में और भी स्कूल जोड़े जाएंगे। इस अवसर पर सीआईएल के अध्यक्ष पीएम प्रसाद, कोयला मंत्रालय में अपर सचिव

रूपिंदर बरार, कोयला मंत्रालय की उप महानिदेशक संतोष, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी समीरन दत्ता, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के सीएमडी नीलेन्दु कुमार सिंह तथा कोयला मंत्रालय और सीआईएल एवं उसकी सहायक कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डॉ. अग्रवाल्स हेल्थ केयर का आईपीओ 29 जनवरी को खुलेगा, प्राइस बैंड 382-402 रुपये प्रति शेयर

मुंबई/नई दिल्ली। डॉ. अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड (डीएएचसीएल) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निवेशकों के लिए 29 जनवरी को खुलेगा और 31 जनवरी को बंद होगा। कंपनी ने इसके लिए मूल?य का दायरा (प्राइस बैंड) 382-402 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने जारी एक बयान में बताया कि डॉ. अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड के आईपीओ सब्सिक्रिप्शन के लिए बड़े निवेशक 28 जनवरी को बोली लगा सकेंगे।

कंपनी के मुताबिक निवेशक इसमें न्यूनतम 35 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 35 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। इस पेशकश के लिए पात्र कर्मचारी भी बोली लगा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक यह आईपीओ 300 करोड़ रुपये तक के नए निर्गम और 2,727.26 करोड़ रुपये मूल्य के 6.78 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। इस प्रकार कुल निर्गम आकार 3,027.26 करोड़ रुपये होगा। इसमें 1,579,399 इक्विटी शेयरों तक का कर्मचारी आरक्षण और 1,129,574 इक्विटी शेयरों तक का शेयरधारक आरक्षण है।

उतार-चढ़ाव के बीच गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 900 अंक टूटा

एजेंसी

नई दिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद लिवालों और बिकवालों के बीच एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से शेयर बाजार की चाल भी ऊपर-नीचे होती रही। इस उतार-चढ़ाव के कारण सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से करीब 900 अंक तक और निफ्टी करीब 300 अंक तक टूट गए। हालांकि अंत में खरीदारी का सपोर्ट मिलने पर दोनों सूचकांक मामूली रिकवरी करने में सफल रहे। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.43 प्रतिशत और निफ्टी 0.49 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए।

आज दिनभर के कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस, रियल्टी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयरों में लगातार बिकवाली होती रही। इसी तरह बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल और पीएसई इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। दूसरी ओर टेक, एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.60 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 2.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ आज के कारोबार का अंत किया।आज शेयर बाजार में आई गिरावट के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 419.61 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 424.63 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 5.02 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,059 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,038 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,902 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 119 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,545 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 482 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान और 2,063 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 10 शेयर बढ़त के साथ और 20 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान में और 32 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 65.03 अंक की कमजोरी के साथ 76,455.35 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के बाद पूरे दिन तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश चलती रही, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा। खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक 465.57 अंक की मजबूती के साथ 76,985.95 अंक के स्तर तक पहुंच गया। दूसरी ओर, बिकवाली का दबाव बनने पर ये सूचकांक ऊपरी स्तर से 894.20 अंक टूट कर 428.63 अंक की कमजोरी के साथ 76,091.75 अंक तक गिर भी गया। हालांकि आखिरी वक्त में हुई खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक निचले स्तर से करीब 100 अंक की रिकवरी करके 329.92 अंक की गिरावट के साथ 76,190.46 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

ट्रंप पहुंचे लॉस एंजिल्स, आग प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, गवर्नर न्यूसम को हर तरह की मदद का दिया भरोसा

एजेंसी

लॉस एंजिल्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप शुक्रवार दोपहर वायुसेना के विशेष विमान से लॉस एंजिल्स पहुंचे। राष्ट्रपति का यहां पहुंचने पर कैलिफोर्निया के गवर्नर और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता गेविन क्रिस्टोफर न्यूसम ने स्वागत किया। इसके बाद ट्रंप ने आग प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रपति पैसिफिक पैलिसेड्स के तटीय लॉस एंजिल्स काउंटी में आग प्रभावित क्षेत्र में हुई तबाही को देखकर अवाक रह गए। सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, ट्रंप ने लॉस एंजिल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टरमैक के पास इंतजार कर रहे पत्रकारों को संबोधित करने से पहले गवर्नर न्यूसम से संक्षेप में बात की। ट्रंप ने न्यूसम को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए न्यूसम की प्रशंसा भी की। गवर्नर न्यूसम ने कहा कि आग प्रभावित क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। इसकी भरपाई बिना सरकारी के मदद के संभव नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हर तरह की संघीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संघीय सरकार पूरी तरह साथ में खड़ी है।

श्रीलंका में मंत्रियों के विशेषाधिकारों में कटौती

कोलंबो। श्रीलंका में मंत्रियों के विशेषाधिकारों में बड़ी कटौती की गई है। सरकार ने मंत्रियों को दिए जाने वाले लाभों को सीमित करते हुए सख्त नियमों की घोषणा की है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने गुरुवार को इस संबंध में परिपत्र जारी किया। इसमें कैबिनेट और उप मंत्रियों के लिए दो सरकारी वाहनों की सीमा तय की है। इसका उद्देश्य राजनीतिक विशेषाधिकार और जवाबदेही पर जनता की चिंताओं को दूर करना है। श्रीलंका के समाचार पत्र डेली न्यूज के अनुसार, राष्ट्रपति के सचिव डॉ. एनएस कुमानायके ने मंत्रालय सचिवों को सलाहकारों और कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय नई प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अभी एक मंत्री के निजी स्टाफ के लिए नियुक्त की जा सकने वाली अधिकतम संख्या 15 है और एक उप मंत्री के निजी स्टाफ के लिए नियुक्त की जाने वाली अधिकतम संख्या 12 है। अब एक मंत्री के लिए दो निजी सहायक, दो समन्वयक सचिव, एक प्रेस सचिव, एक जनसंपर्क अधिकारी, पांच प्रबंधन सहायक, दो कार्यालय सहायक और दो ड्राइवर नियुक्त किए जा सकते हैं। उप मंत्री दो समन्वयक सचिव, तीन प्रबंधन सहायक और अन्य पदों के लिए एक-एक की भर्ती कर सकते हैं। साफ किया गया है कि मंत्री इन पदों पर परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। परिपत्र के अनुसार, मंत्रियों के ईंधन भत्ते, कार्यालय, आवासीय और मोबाइल फोन व्यय के लिए मासिक भुगतान की भी नई सीमा तय की गई।

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों की धरपकड़ तेज, 538 गिरफ्तार

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों की धरपकड़ तेज हो गई है। कुछ दिन पहले देश की दूसरी बार बागडोर संभालने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि देश में एक भी व्यक्ति को अवैध रूप से रहने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि आज 538 अवैध आप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर लिखा है, आज ट्रंप प्रशासन ने एक संदिग्ध आतंकवादी ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के चार सदस्यों और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई लोगों सहित 538 अवैध आप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अरब न्यूज की खबर के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस सचिव लेविट ने गुरुवार देर रात यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सैकड़ों लोगों को सैन्य विमानों के जरिये निर्वासित किया गया। अमेरिका के इतिहास का यह सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है। किए गए वादे निभाए जा रहे हैं। ट्रंप ने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। नेवार्क शहर के मेयर रास जे. बाराका ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) एजेंटों ने एक स्थानीय प्रतिष्ठान पर छापा मारा। यहां से बिना दस्तावेज के रह रहे दूसरे देशों के निवासियों और कुछ स्थानीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया।

महाराष्ट्र रेल हादसे में मारे गए सात नेपाली नागरिकों की शिनाख्त, शवों को स्वदेश लाने की तैयारी

काठमांडू। महाराष्ट्र के जलगांव में 22 जनवरी को हुए रेल हादसे में मरने वाले नेपाली नागरिकों की संख्या 7 पहुंच गई है। सभी मृतकों की पहचान हो गई है। अपने नागरिकों के शवों को स्वदेश लाने के लिए नेपाल सरकार दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के साथ समन्वय कर रही है। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों के ट्रेन से कूदने के बाद हुए हादसे में अब तक सात नेपाली नागरिकों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में सात नेपाली नागरिकों की मौत होने और उन सभी की पहचान होने की जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में नेपाल के अछाम जिले के चार, कैलाली जिले के दो और बांके जिला का एक नागरिक है। इन मृतकों की पहचान अछाम जिला मंगलसेन के 11 वर्षीय हिमुनन्दराम विश्वकर्मा, 44 वर्षीय नन्दराम पद्य विश्वकर्मा, 42 वर्षीया मैसारा कामी विश्वकर्मा और अछाम कमलबजार की 60 वर्षीया जोक्ला उर्फ कला कामी के रूप में हुई है।

इजरायली सेना 60 दिन पूरे होने के बाद भी लेबनान में रहेगी - पीएमओ

एजेंसी

यरूशलम। इजरायल ने घोषणा की कि उसकी सेना युद्धविराम समझौते के 60 दिन के भीतर दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह वापसी नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि इजरायल 26 जनवरी को यह अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां अपनी सेना रखेगा।

बताया जा रहा है कि यह निर्णय 27 नवंबर 2024 को हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि इजरायल को 60 दिन के भीतर अपनी सेना को लेबनान से पूरी तरह से वापस ले लेना चाहिए। यह समय सीमा रविवार को समाप्त हो रही है। हालांकि, नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इजरायल यह समय सीमा को नहीं मानेगा क्योंकि लेबनानी सेना ने अभी तक दक्षिणी लेबनान पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं स्थापित किया है और हिजबुल्लाह ने लिटानी नदी के उत्तर से अपनी सेनाओं को पूरी तरह से पीछे नहीं हटाया है। नेतन्याहू के

कार्यालय ने एक बयान में कहा, लेबनानी सरकार ने संघर्ष विराम समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, इसलिए इजरायली सैनिकों की वापसी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायल की वापसी लेबनानी सेना की तैनाती और समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी, जिसमें हिजबुल्लाह का लिटानी नदी से पीछे हटना भी शामिल है। यह फैसला अमेरिका के साथ समन्वय में लिया गया है, और यह संकेत करता है कि इजरायल की सेनाओं की वापसी का काम धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक किया जाएगा। दक्षिणी इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा हमले और उसके बाद गाजा में इजरायल की जवाबी कार्रवाई के बाद, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पार से गोलीबारी में बढ़ गई थी। इसके बाद, अक्टूबर 2024 में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी आक्रमण किया। इस बीच, कुवैत के विदेश मंत्री और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के प्रमुख ने लेबनान का दौरा किया और युद्ध से तबाह हुए देश के खाड़ी देशों के साथ संबंधों को बहाल करने के प्रयासों के तहत समर्थन का वादा किया। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या ने बेरूत में लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल औन से मुलाकात की और कुवैत की ओर से लेबनान की मदद करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। लेबनानी राष्ट्रपति मिशेल औन ने कुवैत और जीसीसी से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका देश अपने खाड़ी पड़ोसियों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इजरायली महिला सैनिक रिहा होंगी

एजेंसी

यरूशलम। गाजा से संघर्ष विराम समझौते के तहत शनिवार को चार इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उसे हमास से मध्यस्थ देशों के माध्यम से चार इजरायली महिला सैनिकों के नाम मिले हैं जिन्हें संघर्ष विराम समझौते के तहत आज गाजा से रिहा किया जाएगा।इस सूची में 19-20 वर्ष की आयु की सेना पर्यवेक्षक लिरी अलबाग, करीना एरीव, डेनिएला गिल्बोआ और नामा लेवी शामिल हैं, जिन्हें हमास ने सात अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी सीमा के पास नाहल ओज में इजरायली सेना के निगरानी अड्डे से अगवा किया था। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि हमास की सूची समझौते की शर्तों का उल्लंघन करती है। समझौते में कहा गया है कि महिला नागरिकों को किसी अन्य से पहले रिहा किया जाना चाहिए।

हिब्रू मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि इजरायल ने हमास द्वारा नामित चार बंधकों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की और यह तय किया गया कि उल्लंघन इतना गंभीर नहीं था

कि समझौता टूट जाए। इस समझौते की शर्तों के अनुसार इज़रायल को चार सैनिकों के बदले में लगभग 200 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। गाजा युद्धविराम समझौते के तहत यह इज़रायली बंधकों और फ़िलिस्तीनी कैदियों की दूसरी अदला-बदली होगी। इससे पहले रविवार को पहली अदला-बदली में तीन इज़रायली नागरिक महिलाओं और 90 फ़िलिस्तीनी महिलाओं और नाबालिगों को रिहा किया गया था।

जेनिन पर इज़रायली हवाई हमले में दो लोगों की मौत

एजेंसी

रामल्लाह/यरूशलम। उत्तरी वेस्ट बैंक में जेनिन के दक्षिण में कबातिया में एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए इज़रायली हवाई हमले में दो फ़िलिस्तीनी मारे गए। जेनिन के गवर्नर कमाल अबू अल-रब ने कहा कि शहर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास एक इज़रायली ड्रोन ने वाहन पर हमला किया। हमले में वाहन पूरी तरह जल गया। उन्होंने पीड़ितों की पहचान महमूद कामिल और हमूद ज़कारनेह के रूप में की।

इज़रायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह पिछले चार दिनों से उत्तरी वेस्ट बैंक में आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा था। अभियान में आईडीएफ, इज़रायल सुरक्षा एजेंसी और सीमा पुलिस बल शामिल थे। अबू अल-रब ने बताया कि इन मौतों के साथ जेनिन में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक इज़रायली सेना द्वारा मारे

गए फ़िलिस्तीनियों की संख्या 14 हो गई है। इजरायली सेना ने 'आतंकवादी समूहों' को खत्म करने और वेस्ट बैंक में सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए आयरन वॉल नामक अभियान शुरू किया।अक्टूबर 2023 से वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ गया है, जब गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तब से इजरायली सेना और फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष में वेस्ट बैंक में 800 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।

टिकटॉक वीडियों बनाने वाला व्यक्ति शेर का बच्चा रखने के आरोप में गिरफ्तार

एजेंसी

लाहर। पाकिस्तान के पंजाब वन्यजीव विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के बाद टिकटॉक वीडियों बनाने वाले रजब बट को लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पिछले महीने कानूनों का उल्लंघन कर शावक को रखने की बात स्वीकार की थी।

'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी एक वन्यजीव अधिकारी द्वारा लाहौर में एक स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने तब कार्रवाई की जब एक वीडियो सामने आया जिसमें बट को शादी के तोहफे के रूप में एक नवजात शेर का बच्चा लेते हुए दिखाया गया, जिससे वन्यजीवों के अवैध कब्जे पर चिंता बढ़ गई। अदालत के फैसले के मुताबिक बट

को एक साल तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में सामुदायिक सेवा प्रदान करनी होगी। अपनी सेवा के हिस्से के रूप में, बट पशु अधिकारों पर चर्चा करते हुए व्लॉग बनाएंगे। पशु संरक्षण और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, परिवीक्षा अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ये वीलॉग मासिक रूप से अपलोड किए जाएंगे।

चीन ने शीत लहर और घने कोहरे के लिए अलर्ट जारी किया

एजेंसी

बीजिंग। चीन ने शीत लहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चीन के मौसम विज्ञान प्राधिकरण ने शीत लहर के लिए येलो अलर्ट को नवीनीकृत किया। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन दिनों में तापमान में 8-12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जाएगी। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनएमसी) ने कहा कि इस अवधि के दौरान उत्तर-पश्चिमी चीन के पूर्वी हिस्से के कुछ क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तरी चीन और सिचुआन पठार के पश्चिमी हिस्सों में 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट का अनुभव होने की संभावना है। एनएमसी ने लोगों को गर्म रहने की सलाह दी है और फसलों और जलीय उत्पादों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का आह्वान किया है। केंद्र ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट को भी नवीनीकृत किया एवं चेतावनी दी कि से शाम तक किओन्गझोउ जलडमरूमध्य, लीझोउ प्रायद्वीप और गुआंगशी के तटीय जल सहित कुछ क्षेत्रों में दृश्यता एक किलोमीटर से कम हो जाएगी और कुछ मामलों में

500 मीटर से भी कम हो जाने की संभावना है। केन्द्र ने चालकों को सुरक्षित गति बनाए रखने के लिए कहा है जबकि हवाई अड्डों, फ्रीवे और बंदरगाहों को उचित सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया गया है। चीन में गंभीर मौसम के लिए चार-स्तरीय रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली है जिसमें लाल सबसे गंभीर है।

यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में तेल संयंत्रों और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र पर किया ड्रोन हमला

एजेंसी

कीव। यूक्रेनी सेना ने शुक्रवार रात पश्चिमी रूस में तेल संयंत्रों और एक माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र पर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने फेसबुक पर इसकी पुष्टि की। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमले के कारण रियाजान तेल शोधन कंपनी और रियाजान तेल पम्पिंग स्टेशन के उत्पादन संयंत्रों में आग लग गई।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, ड्रोन हमले यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और विशेष अभियान बलों द्वारा अन्य इकाइयों के सहयोग से किए गए। इससे पहले मास्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा था कि मास्को की वायु रक्षा प्रणालियां शुक्रवार की सुबह यूक्रेनी ड्रोन हमलों को रोकने में सक्रिय रूप से लगी हुई थीं। सोबयानिन ने लिखा कि ड्रोन हमले मास्को के आसपास के कई स्थानों पर हुए जिनमें राजधानी के दक्षिण-

पूर्व में स्थित कोलोम्ना और रामेंस्की शहरी जिले भी शामिल हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि घटना स्थल पर कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई है। उन्होंने लिखा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तुरंत प्रभावित स्थलों पर भेज दिया गया।पोडोल्स्क शहरी जिले में मास्को की ओर बढ़ते हुए दो अतिरिक्त ड्रोनों को वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद में दुष्प्रचार निरोधक केन्द्र के प्रमुख आंद्रेई कोवलेंको ने दावा किया था कि यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी रूस के स्मोलेंस्क क्षेत्र में स्थित एक रूसी विमानन संयंत्र पर हमला किया था। कोवलेंको ने मंगलवार को कहा कि संयंत्र सैन्य विमानों और विशेष रूप से एसयू-25 हमलावर विमानों के उत्पादन में भाग लेता है। जिसमें विमानन उपकरणों का रखरखाव भी शामिल है। उन्होंने कहा, ÷यह संयंत्र रूसी रा उद्योग के अन्य उद्यमों से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो आधुनिक विमानन प्रणालियों के निर्माण के लिए घटकों की आपूर्ति करता है या सहयोग में भाग लेता है। कोवलेंको ने हमले में इस्तेमाल किये गये साधनों का खुलासा नहीं किया।

अमेरिकी सीनेट ने जॉन रैटक्लिफ को सीआईए डायरेक्टर के रूप में दी मंजूरी

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) जॉन रैटक्लिफ को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त करने के पक्ष में वोट किया है। समाचार एजेंसी के अनुसार, सीनेट गुरुवार को 25 के मुकाबले 74 वोट से रैटक्लिफ के नामांकन को मंजूरी दी। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी आठ महीनों में ट्रंप के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में काम किया। इस खबर की पुष्टि करते हुए, व्हाइट हाउस ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की और लिखा, जॉन रैटक्लिफ की सीआईए के निदेशक के रूप में पुष्टि, विश्व मंच पर अमेरिका की ताकत को बहाल करने के राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। डीएनआई निदेशक के रूप में,

रैटक्लिफ ने चीन पर निर्णायक रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अमेरिकी खुफिया समुदाय की प्राथमिकताओं में बदलाव का नेतृत्व किया। साथ ही आतंकवाद का समर्थन करने वाले अनेक नेताओं को हटाने के लिए कई अभियानों की निगरानी की। निदेशक रैटक्लिफ ने अमेरिकी खुफिया समुदाय के 18वें सदस्य के रूप में अमेरिकी अंतरिक्ष बल को जोड़कर अंतरिक्ष को प्राथमिकता वाले खुफिया डोमेन में बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया। व्हाइट हाउस के अनुसार, खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा पदक प्राप्त किया। कांग्रेस के सदस्य के रूप में, रैटक्लिफ हाउस इंटेलिजेंस, होमलैंड सिक्योरिटी और न्यायपालिका समितियों के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एक अग्रणी नीति निर्माता रहे। रैटक्लिफ ने पहले 2015 से 2020 तक टेक्सास के चौथे कांग्रेसनल जिले के लिए यूएस हाउस के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। रैटक्लिफ के नामांकन का समर्थन करने में 21 डेमोक्रेट सांसदों ने रिपब्लिकन का समर्थन किया। हुआ यह मतदान सीनेट द्वारा फ्लोरिडा से अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो को राज्य सचिव के रूप में सर्वसम्मति से नियुक्ति के तीन दिन बाद हुआ।

जल्द से जल्द पुतिन से मिलना चाहता हूं, लाखों जिंदगियों का सवाल है ; रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए समझौते के लिए तैयार हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी उनके पिछले बयान से काफी अलग है। इस हफ्ते की सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने धमकी थी कि अगर मॉस्को समझौता नहीं करता है तो वह रूस पर 'उच्च स्तर' के प्रतिबंध लगा देंगे और वहां से आयात पर शुल्क लगा देंगे। 5 नवंबर को चुनाव जीतने से पहले ट्रंप ने कई बार दावा किया कि वह पहले दिन ही यूक्रेन और रूस के बीच समझौता कर लेंगे। हालांकि अब उनके सलाहकार मानते हैं कि युद्ध को सुलझाने में महीनों लग जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच को वीडियो लिंक के

जरिए संबोधित करते हुए कहा, मैं वास्तव में जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहूंगा ताकि युद्ध समाप्त हो सके।और यह अर्थव्यवस्था या किसी अन्य चीज के नजरिए से नहीं कह रहा हूं। यह इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही हैं... यह एक नरसंहार है। और हमें वास्तव में युद्ध को रोकना होगा। बाद में व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने मीडिया से कहा कि वह इस हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा, ÷मैंने जो सुना है, उसके अनुसार पुतिन मुझसे मिलना चाहेंगे। उन्होंने ने दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उनसे कहा था कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता करने के लिए तैयार हैं।

खालिदा जिया को लंदन में अस्पताल से बेटे के घर शिफ्ट करने की तैयारी

लंदन। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को अस्पताल से उनके बेटे तारिक रहमान के लंदन स्थित किंग्स्टन निवास पर शिफ्ट किया जाएगा। उनके निजी चिकित्सक ने कहा कि वयोवृद्ध बेगम खालिदा जिया का इलाज अब तारिक रहमान के घर पर होगा। बेगम खालिदा इस समय द लंदन क्लिनिक में भर्ती हैं। बांग्लादेश के समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, बेगम खालिदा के निजी चिकित्सक और बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य डॉ. एजेडएम जाहिद हुसैन ने गुरुवार को स्थानीय समयानुसार रात करीब 10ः30 बजे द लंदन क्लिनिक के सामने पत्रकारों से यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया शुक्रवार रात को बेटे के घर जा सकती हैं। घर पर डॉ. पैट्रिक कैनेडी और डॉ. जेनिफर क्रॉस की देखरेख में उनका इलाज जारी रहेगा। उन्होंने खालिदा जिया के ठीक होने की प्रार्थना की है। डॉ. जाहिद ने कहा कि अगर उनकी सेहत में सुधार इसी दर से जारी रहा तो वह जल्द ही बांग्लादेश लौट सकती हैं। हालांकि डॉ. जाहिद ने साफ किया कि लीवर प्रत्यारोपण के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ढाका ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि खालिदा जिया की उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए लिवर प्रत्यारोपण की संभावना फिलहाल कम है।

डोनाल्ड ट्रंप को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश पर अदालत ने लगाई रोक

एजेंसी

वाशिंगटन । एक फेडरल जज ने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। जज ने इस आदेश को 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' बताया।

इस बीच, ट्रंप ने अदालत के आदेश पर कहा, 'जाहिर है कि हम अपील करेंगे।' एमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिएटल स्थित अमेरिकी जिला जज जॉन कफनौर ने चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों - वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन - की अपील पर एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया। रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त जज ने इमिग्रेशन पर ट्रंप प्रशासन की कठोर नीतियों को पहला कानूनी झटका दिया। बता दें ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान अवैध प्रवासियों का मुद्दा बार-बार उठाया था। न्यायाधीश ने ट्रम्प के आदेश का बचाव करने वाले अमेरिकी न्याय विभाग के वकील से कहा, 'मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि बार का एक सदस्य स्पष्ट रूप से कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह मेरे दिमाग को चकरा देता है।' इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति

ने जन्मसिद्ध नागरिकता के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए इसे 'बिल्कुल हास्यास्पद' अवधारणा करार दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका 'दुनिया का एकमात्र देश' है, जिसके पास ऐसा नियम है। कार्यकारी आदेश के मुताबिक अमेरिका में जन्मे बच्चे - [जिनके माता-पिता में से कम से कम एक नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं है] - को अब स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।

यह फेडरल एजेंसियों को ऐसे बच्चों के लिए अमेरिकी नागरिकता साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज जारी करने या मान्यता देने से भी रोकता है। यह आदेश अनधिकृत अप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर अमेरिका में वैध रूप से रहने वालों के बच्चों को लक्षित करता है। अगर यह आदेश पारित हो जाता है तो अस्थायी वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने आदेश पर जब से हस्ताक्षर किए हैं, तब से इसे चुनौती देते हुए कम से कम छह मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक अधिकार समूहों और 22 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर किए गए हैं।

स्थानीय समाचार

उपराज्यपाल जम्मू में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शामिल हुए

जम्मू 25 जनवरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भाग लिया।

उपराज्यपाल ने भारत के चुनाव आयोग से प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू-कश्मीर और उनकी टीम को बधाई दी।

उन्होंने लोकसभा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के निष्पक्ष, पारदर्शी और सफल संचालन के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों, राष्ट्रीय चुनाव आयोग और चुनाव विभाग के अधिकारियों, पुलिस और सुरक्षा बलों, अधिकारियों और सभी हितधारकों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।

उपराज्यपाल ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक मतदान जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ आस्था और नागरिक भागीदारी की नई भावना और एक नए युग की आशा को दर्शाता है, जिसमें लोगों की इच्छा से प्रेरित होकर लोकतंत्र पहले से कहीं अधिक गहराई से जड़ें जमा रहा है।

चुनाव आयोग के बहुमूल्य योगदान पर प्रकाश डालते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक योजना और निरंतर निगरानी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस बार जम्मू-कश्मीर चुनाव सुचारू और सुव्यवस्थित रहे हैं, जिसमें कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि यह जम्मू कश्मीर में सबसे निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और शानदार चुनाव था।

उपराज्यपाल ने कहा, हमारा सांस्कृतिक लोकाचार स्वतंत्रता, समानता और समावेशिता के लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित है और अपने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देता है। हमारे देश में लोगों की इच्छा एक सदियों पुरानी अवधारणा है और इसीलिए भारत को 'लोकतंत्र की जननी' कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा प्रत्येक वोट की शक्ति को रेखांकित करती है और इस बात पर जोर देती है कि मतदान सभी बाधाओं को पार करता है, जो मतदान के अधिकार की सच्ची भावना को दर्शाता है।

उन्होंने कहा भारतीय लोकतंत्र वास्तव में सहयोग, सहभागिता, शांति और लोगों की सामूहिक शक्ति का उत्सवी उद्घोष है। भारत उन चुनिंदा देशों में से है, जहां लोकतांत्रिक आदर्श सबसे मजबूत और सर्वोपरि हैं। मुझे गर्व है कि आज ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के कई देश भारत से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के तरीके सीख रहे हैं।

उपराज्यपाल ने परिसीमन के बाद मतदाता सूची के सफल सारांश संशोधन और 89 लाख मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार करने और सभी 11,838 मतदान केंद्रों पर पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इन चुनावों के दौरान मतदाता मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश की चुनाव मशीनरी के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समाज के सभी वर्गों को अपने वोट की ताकत के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य योग्य युवाओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है।

उपराज्यपाल ने डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह और एसएसपी पुलवामा पी.डी. नित्या को भी बधाई दी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के लिए सम्मानित किया गया है।

इस अवसर पर उपराज्यपाल ने अधिकारियों और लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई।

उपराज्यपाल ने जम्मू की डीआईजी आई.आर. सारा रिजवी, बारामुल्ला के उपायुक्त मिंगा शेरपा, जम्मू के उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य, किश्तवाड़ के उपायुक्त राजेश कुमार शवन, जेएमसी के कमिश्नर देवांश यादव, एसएसपी साहिल सारंगल, एसएसपी रणदीप कुमार, संयुक्त सीईओ अनिल सलगोत्रा और पुलिस तथा अन्य हितधारक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को लोकसभा और जम्मू-

कश्मीर विधानसभा चुनावों के सफल संचालन में उनके योगदान के लिए यूटी-स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया।

उपराज्यपाल ने एक मोबाइल वाहन डेमोक्रेसी ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई, जो छात्रों को मतदान और चुनाव प्रक्रिया के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अभिनव उपकरण के रूप में काम करेगा।

उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार ने बडगाम का दौरा किया

बडगाम 25 जनवरी। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी के साथ बडगाम जिले का व्यापक दौरा किया।

सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह और विधायक चडूरा अली मोहम्मद डार, बडगाम के उपायुक्त अक्षय लाबरू, मुख्य अभियंता और विभिन्न विभागों के अन्य सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दूरदराज और उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के अलावा लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदलने हेतु पहल को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा, हम गुणवत्तापूर्ण कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी के साथ तेज गति और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह स्थानीय जरूरतों और क्षेत्र विशेष के विकास के अनुसार किया गया है। जनता की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बडगाम को 4 लेन की सड़क बनाने की घोषणा की।

उन्होंने डीसी कार्यालय से हुमहामा तक सड़क का सर्वेक्षण करने के अलावा चरण-1 में डीसी कार्यालय से न्यू बस अड्डा तक सड़क को 4 लेन चौड़ा करने के लिए डीपीआर तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार ने वर्तमान सरकार द्वारा अपने गठन के बाद से किए गए विभिन्न विकासात्मक पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक समग्र विकासात्मक एजेंडा चल रहा है जो जम्मू-कश्मीर में बदलाव सुनिश्चित करेगा।

छत पर उगाएं सब्जियां

जय प्रकाश जय

ये कैसा जमाना आ गया कि गांवों में खेतों में मकान बन रहे हैं और शहरों में मकानों पर खेती हो रही है। यह एक अजीब तरह का विरोधाभास भी है और सुखद भी कि बेरोजगारी, महंगाई के कठिन वक्त में जागरूक लोग अपने घर की छत पर फल-फूल, सब्जियों, फसलों की खेती कर परिवार का पोषण करने के साथ ही लगे हाथ सालाना लाखों की नकद कमाई भी कर रहे हैं।

आईआईटी ग्रेजुएट कौस्तुभ खरे और साहिल पारिख बाकायदा खेतीफाई नाम से अपनी बिजनेस कंपनी बनाकर मात्र उन्नीस हजार की लागत से दो सौ वर्ग मीटर की छत पर सात-आठ सौ किलो सब्जियां उगा रहे हैं।

यह सुखद दास्तान किसी एक शहरी किसान की नहीं। छत्तीसगढ़ की पुष्पा, पानीपत (हरियाणा) के कृष्ण कुमार, हिसार के हरबंस सिंह, दिल्ली के संतोष आदि इसी तरह की किसानी से हरे-भरे हो रहे हैं। अब तो कई उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बाकायदा इस तरह की खेती के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण में जुट गए हैं। कंपनी बनाकर वह छतों पर खेती करवा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में निशांत चौधरी, आईआईटी ग्रेजुएट कौस्तुभ खरे, साहिल पारिख आदि। दिल्ली में तिब्बती रिफ्यूजी कॉलोनी के पीछे यमुना नदी के किनारे खेती कर रहे संतोष बताते हैं कि छत पर खेती करना ज्यादा आसान है। दिल्ली में तमाम मकानों की छतों पर इस तरह की खेती हो रही है।

अंबेडकर यूनिवर्सिटी में फेलो इन एक्शन रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस के निशांत चौधरी बताते हैं कि दिल्ली में जो किसान यमुना किनारे खेती करते हैं उन पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई का खतरा रहता है। इसीलिए, उन्होंने किसानों के लिए %क्यारी% नाम से एक नया मॉडल तैयार किया, जो मजबूत मैटेरियल से बना एक तरह का बस्ता होता है। इसमें नारियल का सूखा छिलका होता है। छत पर भार, पानी रिसाव से बचने के लिए बिना मिट्टी वाले इस बस्ते में उपजाऊपन बढ़ाने के लिए कंपोस्ट, बारह किस्म के और भी मिश्रण होते हैं।

इसमें केमिकल की जगह पारंपरिक कीटनाशक छाछ, नींबू, मिर्ची आदि का इस्तेमाल होता है। उन्हें इस मॉडल की प्रेरणा केरल से मिली। छत पर खेती की क्यारियां वॉटर प्रूफ होती हैं। चार फीट के एक बस्ते में गर्मियों में पांच लीटर पानी दिन में दो बार, सर्दियों में दो दिन में एक बार दिया जाता है।

निशांत इस समय यमुना किनारे खेती करने वाले लगभग दो दर्जन किसानों को छत पर खेती के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं। ये किसान छतों पर भिंडी, टमाटर, बैंगन, मेथी, पालक, चौलाई, पोई साग और मिर्च उगा रहे हैं। आईआईटी ग्रेजुएट कौस्तुभ खरे और साहिल पारिख बाकायदा %खेतीफाई% नाम से अपनी बिजनेस कंपनी बनाकर मात्र उन्नीस हजार की लागत से दो सौ वर्ग मीटर की छत पर सात-आठ सौ किलो सब्जियां उगा रहे हैं। इनका मॉडल भी बिना मिट्टी-पानी वाला है। उन्होंने भी छत पर खेती करने के लिए वॉटर प्रूफ क्यारियां बनाई हैं। जैविक सामग्री से लैस इन क्यारियों में भिंडी, टमाटर, बैंगन, मेथी, पालक, चौलाई, पोई साग और मिर्च उगाई जा रही हैं।

ये तो रही तकनीकी तरीके से नए मॉडल विकसित कर छतों पर खेती कराने की पहल, लेकिन अन्य राज्यों में तमाम किसान अपनी सीमित छतों पर इसी तरह सब्जियों की खेती कर रहे हैं। जैसे पानीपत (हरियाणा) के कृष्ण कुमार। वह पेशे से किसान नहीं हैं। जब वह रेलवे नौकरी से रिटायर हुए तो अपनी कोई खेती-बाड़ी न होने के कारण दो गज के मकान की छत पर बागवानी करने लगे। मछली के वेस्ट थर्मोकोल की ट्रे बनाई और उसमें फलों और सब्जियों का उत्पादन शुरू कर दिया। करीब दो दशक से वह छत पर बागवानी कर रहे हैं। वह सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, घरौंडा से सब्जी और सहारनपुर (यूपी) से फलदार पेड़ों की पौध लाते हैं। जहां भी बागवानी विभाग के मेले लगते हैं वहां जाना नहीं भूलते।

आक, तंबाकू आदि से वह खुद का जैविक घोल तैयार कर पौधों को कीट और फसल बीमारियों से बचाते हैं। इस सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। अब तो वह रोजाना छह-सात किलो टमाटर का उत्पादन हो रहा है। साथ ही बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी, भिंडी, धनिया भी उगा रहे। छत पर ही गमलों में अमरूद, अनार, चीकू, सेब, आडू, चेरी आदि फल पैदा हो रहे हैं, जिनमें नौ प्रकार के अमरूद, तीन तरह के अनार, पांच तरह के आडू, चेरी, सेब आदि के फल मिल रहे हैं। इसी तरह हरियाणा के उपमण्डल टोहाना के गांव जापतावाला के किसान हरबंस सिंह जुगत लड़ाकर अपने घर की छत पर विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उनके घर की छत पर तैयार सब्जियों की फसल से न केवल उसके परिवार के सदस्य दोनों समय की ताजा व बिना कीटनाशकों के छिड़काव वाली सब्जियां खा रहे हैं बल्कि इस समय छत पर मिर्च, मटर, बैंगन, अंगूर, गोभी, चोले, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया, पालक, मूली और गाजर की पैदावार भी ली जा रही है।

सब्जियों को कीटनाशक व रासायनिक खाद रहित जैविक तकनीक से पैदा किया गया है। पांचवीं तक पढ़े हरबंस बताते हैं कि बचपन से ही उनका सब्जियां उगाने का शौक रहा है। खेती की जमीन कम होने के कारण उन्होंने किसानी का ये तरीका खुद विकसित किया। छत पर ही ट्रे और गमलों में बेल वाली सब्जियों को रोपाई करने लगे। आज करीबन एक दर्जन किस्म की सब्जियां उनकी छत पर पैदा हो रही हैं। उनके पास मात्र एक एकड़ भूमि है, जिसमें फसलों की खेती करते हैं। उनकी छत पर ज्यादातर हाइब्रिड बीजों वाली सब्जियां पैदा हो रही हैं।

छत्तीसगढ़ की किसान पुष्पा साहू अपने घर की छत पर फल, फूल और सब्जियों के साथ औषधीय फसलों की बागवानी भी कर रही हैं। वह बताती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में खास कर कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने एवं घरेलू महिलाओं तथा बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में छत पर फलों, साग-सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती एक नई संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। किचन डिजाइनर पॉट्स में भी किचन प्लांट्स लगा सकते हैं। अपने घर को आर्टिस्ट लुक देना सभी को खूब भाता है। छत पर खेती करना सामान्य खेती करने से अलग है। छत पर गीली मिट्टी बिछाकर खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि पानी रिसाव (सीपेज) से छत एवं मकान को क्षति पहुंचती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाया जा सकता है, जैसे सीपेज रोधी केमिकल की कोटिंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाली पॉलीथिन शीट बिछाकर क्यारी का निर्माण किया जा सकता है।

वह अपने घर की छत पर सब्जी और फलों की खेती कर रही हैं। छत पर गोभी, बैंगन, कुंदरू, कांदा भाजी, टमाटर, लौकी, मिर्ची पालक भाजी, मूली, धनियां, पुदीना आदि सब्जियों, गेंदा, गुलाब, मोंगरा, नीलकमल आदि पुष्पों के साथ ही सेब, अमरूद, केला, आम, मौसबी, नींबू, चीकू, पपीता और मुनगा फलों की खेती कर रही हैं। मात्र दो-तीन हजार रुपये खर्च कर उनका पूरा परिवार साल भर मौसमी जैविक सब्जियों और फलों का स्वाद ले रहा है। घर की छत पर बिना रासायनिक खाद के उगीं सब्जियां खाने का मजा ही कुछ और होता है। तमाम लोग अब दिल्ली, मुम्बई में अपने फ्लैट की छतों पर सीमित जगह में पुराने सिंक, टब, बाल्टियों, बोरियों, डिब्बों, पेटियों में मेथी, पालक, हरा धनिया, पुदीना, सलाद ही नहीं, टमाटर, बैंगन व गोभी आदि भी सब्जियां उगा रहे हैं। वे पुराने व्यर्थ पड़े सिंक, टब, बाल्टियों, लकड़ी की पेटियों के साथ-साथ छत पर ही नीचे प्लास्टिक की मोटी चादर बिछा कर उस पर शाक वाली सब्जियां लगा रहे हैं। इस विधि से खेती में पानी के निकास की व्यवस्था पर खास ध्यान होना चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी के बड़े गमलों के साथ-साथ इस व्यर्थ कबाड़ का सदुपयोग भी कर सकते हैं। पेंट, डिस्टेंपर आदि की व्यर्थ इकट्ठी होती बाल्टियों, पेंट के बड़े-बड़े डिब्बों के नीचे आपको कम से कम तीन छेद अवश्य बनाने चाहिए, ताकि पानी का निकासी होती रहे। पात्र कोई भी चुनें, उसमें पानी के निकास की भरपूर व्यवस्था अवश्य करें। खाद मिट्टी दूसरा चरण है। छेद पर कम से कम दो इंच मिट्टी के ठीकरे अवश्य बैठाएं। इससे फालतू पानी भी सूख जाता है और निकल भी जाता है। खाद मिट्टी की व्यवस्था के लिए वही नियम लागू होता है, जो फूलों के गमलों के लिए। मिट्टी भारी व चिकनी नहीं होनी चाहिए। दो भाग पुरानी मिट्टी, एक भाग गोबर की अच्छी पुरानी खाद व एक भाग पत्ती की पुरानी खाद व कुल तैयार खाद में दसवां भाग नीम की खली का चूरा मिला दें।

यदि मिट्टी थोड़ी भारी लग रही है तो नदी की बालू रेत या बदरपुर की मोटी बजरी वाली एक भाग मिला दें, ताकि मिट्टी हल्की हो जाए व पानी की निकासी होने से जड़ों के विकास में सहायता मिले। मिट्टी न मिलने की स्थिति में नदी की मोटी वाली बालू रेत अथवा बदरपुर की मोटी वाली बजरी में पत्ती व गोबर की खाद मिला कर सब्जियों को सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है। जिस तरह से खेती के लिए जमीन कम हो रही हैं, भविष्य में इस तरह की खेती का चलन बढ़ते जाना है। चार फीट गुणा चार फीट की चार क्यारियां लगाने पर एक परिवार अपने महीने भर की जरूरत की सब्जी उगा सकता है। एक घंटा इन क्यारियों में समय लगाने से मन लायक सब्जी उगाई जा सकती है।

खेतों के घटने और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट की मांग बढ़ने से अर्बन फार्मिंग में नई और कारगर तकनीकों का चलन बढ़ता जा रहा है। मांग पूरी करने के लिए कारोबारी और शहरी किसान छतों पर, पार्किंग में या फिर कहीं भी उपलब्ध सीमित जगह का इस्तेमाल पैदावार के लिए कर रहे हैं। ये खेती की हाइड्रोपानिक्स विधि है। इस तरीके से ये लोग एक लाख रुपए की लागत से घर बैठे सालाना दो लाख तक की सब्जियां उगा रहे हैं। एक पॉड से साल भर में पांच किलो सलाद पत्ते की उपज मिल सकती है। ऐसे में 10 टावर यानि 400 पॉड से 2000 किलो सालाना तक उपज मिल रही है। हमारे देश में इस समय सलाद पत्ता 180 रुपए किलो है। थोक में सौ रुपए किलो भी मिलता है तो साल में दो लाख रुपए की उपज संभव है।

पृष्ठ 1 का शेष

'पुलिस एवं सुरक्षा बलों'

5. हमारी यात्रा दृढ़ संकल्प एवं हर एक क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों की यात्रा है। अपनी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति के साथ जम्मू-कश्मीर सदैव इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

6. पिछले वर्ष अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव के लिए मैं सभी निर्वाचन अधिकारियों, सुरक्षाबलों, मतदाताओं तथा राजनैतिक दलों को बधाई देना चाहता हूँ। आम नागरिकों ने अलगाववादी तत्वों के एजेंडे को खारिज कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की।

7. आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। ईज़ ऑफ लिविंग के साथ वह एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक समावेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे।

8. गुड गवर्नेंस के मूल्यों को अपनाकर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की सुव्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य डेवलपमेंट गैप्स को समाप्त करना तथा पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करना है।

9. आम नागरिकों को 1,166 ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 501 ई-सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ तथा 387 ई-सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिकों के डाक्यूमेंट की सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के लिए 104 सरकारी सेवाओं को डिजीलॉकर के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

10. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स का 100% सुनिश्चित किया जा रहा है। सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 23 जुलाई 2024 को जेके समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्रतिदिन लगभग 300 शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा शुरू किया गया रावता एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशासन और आम लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है।

11. जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी 2.45 लाख करोड़ रुपये पहुँच गई थी। वर्तमान वित्त वर्ष में जीडीपी के 2.63 लाख करोड़ रुपये पहुँचने का अनुमान है। यह पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी आर्थिक विकास की रणनीतियों, बुनियादी ढांचे की प्रगति और व्यापार-अनुकूल नीतियों का परिणाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल किया है।

12. यूनिफाइड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, निष्पक्षता, समानता, ईज़ ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर में परिवर्तनकारी तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजीकल अपग्रेडेशन किए गए हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किए गए हैं, इंवेस्टिगेटर्स एवं प्रासेक्यूटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है तथा साइबर एवं फोरेंसिक लैब्स की क्षमता को बढ़ाया गया है।

13. प्यारे भाइयो और बहनों, बीते वर्षों में जम्मू-कश्मीर ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक प्रशासन हर क्षेत्र में विकास और समानता के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

ऊंची आर्थिक विकास

गया है जो आने वाले दशकों में विकास को संबल प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, हसंविधान लागू होने के बाद के ये 75 वर्ष हमारे युवा गणतंत्र की सर्वांगीण प्रगति के साक्षी हैं। स्वाधीनता के समय और उसके बाद भी देश के बड़े हिस्से में घोर गरीबी और भुखमरी की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन, हमारा आत्म-विश्वास कभी डिगा नहीं। हमने ऐसी परिस्थितियों के निर्माण का संकल्प लिया जिनमें सभी को विकास करने का अवसर मिल सके। हमारे किसान भाई-बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई-बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थ-व्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत, अंतर- राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है।ऋ

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसी वित्तीय समर्थन योजनाओं का विस्तार किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है कि सरकार ने जन-कल्याण को नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार आवास और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को अधिकार माना गया है। वंचित वर्गों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए प्री- मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय फ़ेलोशिप, विदेशी छात्रवृत्तियां, छात्रावास और कोचिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना द्वारा रोजगार और आमदनी के अवसर उत्पन्न करके अनुसूचित जातियों के लोगों की गरीबी को तेजी से कम किया जा रहा है। अनुसूचित-जनजाति-समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान - पीएम-जनमन - शामिल हैं। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए 'विकास एवं कल्याण बोर्ड' का गठन किया गया है।

एसआईटी ने राजौरी में

का सही कारण जानने के लिए पुलिस जांच के साथ-साथ एक केंद्रीय टीम भी स्वतंत्र जांच कर रही है। दोनों टीमें यह पता लगाने के लिए काम कर रही हैं कि न्यूरोटॉक्सिन जानबूझकर दिए गए थे या किसी और तरीके से।

जम्मू-कश्मीर पुलिस पर पुरस्कारों की बौछार,

10 अन्य अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कश्मीर में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विजय कुमार ने एक इनपुट तैयार किया था कि आतंकवादियों का एक समूह जून 2022 में वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की योजना बना रहा है। 14 जून को कुमार की देखरेख में श्रीनगर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश बलवाल के नेतृत्व में एक छोटे पुलिस दल ने शहर के बाहरी इलाके बेमिना में एक वाहन को रोका, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने कहा कि सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों की सहायता के बिना किए गए ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी सहित दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया गया। विजय कुमार जिन्हें बाद में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया और हाल ही में एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के दिल्ली खंड में स्थानांतरित किया गया है। विजय कुमार, राकेश बलवाल और पांच अन्य पुलिस कर्मियों को उनकी बहादुरी के लिए वीरता पदक मिला। कुमार एक असाधारण अधिकारी हैं जिनके सेवा रिकॉर्ड में जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर आतंकवाद-रोधी, माओवाद-रोधी और कानून-व्यवस्था अभियानों में विशेषज्ञता का एक अनूठा संयोजन शामिल है। उन्होंने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकी खतरों का मुकाबला करने और शांति बनाए रखने की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। सिन्हा ने एक्स के माध्यम से कहा कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों को हार्दिक बधाई।

उन्होंने चयन-ग्रेड फायरमैन सतीश कुमार रैना को भी श्रद्धांजलि दी जिन्हें जम्मू के प्रेम नगर इलाके में आग की घटना के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया था।

जम्मू शहर के शहीदी चौक फायर स्टेशन में तैनात रैना ने जनवरी 2023 में एक अग्निशमन अभियान के दौरान अपनी जान गंवा दी। वीरता पदक वीरता के दुर्लभ विशिष्ट कार्य के लिए क्रमशः जीवन और संपत्ति बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए दिया जाता है जिसमें संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों के संबंध में जोखिम का अनुमान लगाया जाता है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक सेवा में विशेष विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है और सराहनीय सेवा के लिए पदक संसाधन और कर्तव्य के प्रति समर्पण की विशेषता वाली मूल्यवान सेवा के लिए दिया जाता है।

गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता पदक (जीएम) के लिए पुरस्कार विजेताओं में अजहर रशीद पुलिस उपाधीक्षक; माजिद अफजल वानी हेड कांस्टेबल; सफीर लोन कांस्टेबल; शाहनवाज अहमद दीदाद कांस्टेबल; सुरेश कुमार भट सहायक उप-निरीक्षक; अकीब कयूम यट्टू एसजीसीटी; मंजूर अहमद बजाड़ एसजीसीटी; विजय कुमार आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक; राकेश बलवाल आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जीएम); इफ्तखार तालिब पुलिस अधीक्षक; फ़रोज़ अहमद डार सहायक उप-निरीक्षक; सुदीश सिंह हेड कांस्टेबल; पवन कुमार हेड कांस्टेबल; इरशाद अहमद लोहार एसजीसीटी तथा स्वर्गीय हिमायूं मुजम्मिल पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं।

15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस

इसके अलावा, 25 जनवरी भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना दिवस है, जो 1950 में अस्तित्व में आया था और 2025 में इसके अस्तित्व का 75वां वर्ष होगा। यह दिवस पहली बार 2011 में युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था।

चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के नामांकन को बढ़ाना है, विशेषकर उन युवाओं को जो हाल ही में 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु में पात्रता प्राप्त कर चुके हैं।